MOTION *RE* SHORTAGE OF SUGAR IN THE COUNTRY

श्री ए० बी० वाजपेयी (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"चीनी के अभाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार किया जाय ।"

देश के सामने इस समय चीनी संकट विद्यमान है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता । एक दृष्टि से देखें तो यह संकट दोहरा है—सीमा पर भी चीनी संकट है, देश के भीतर भी चीनी संकट है । सीमा पर चीनी संकट इसलिये है कि चीनी अधिक हैं और देश के भीतर चीनी संकट इसलिये है कि चीनी कम हैं । चीनी अगर अधिक हों तो भी संकट और चीनी अगर कम हों तो भी संकट । यह बात देश के भीतर भी लागू होती है ।

बड़े खेद की बात है कि शासन अभी तक चीनी के सम्बन्ध में कोई दूरगामी नीति नहीं बना सका है । हमें प्रतिवर्ष कितनी चीनी की आवश्यकता है, बढ़ती हुई खपत के साथ उस आवश्यकता को कैसे पूरा किया जायगा, उसके अनुसार मिलों को गन्ना किस तरह से मिलेगा, गन्ने की पैदावार किस तरह से बढ़ेगी, शासन इस सम्बन्ध में कोई सुविचारित, तर्कसंगत नीति का निर्धारण नहीं कर सका है । चीनी के सम्बन्ध में जो भी नीति है वह संकट को देख कर तैयार होती है । चीनी की पैदावार बढ़ जाती है तो फिर पैदावार कम करने के लिये कानून बनाए जाते हैं । उस समय इस बात का विचार नहीं किया जाता कि इस बढ़ी हुई पैदावार का हम "बफर स्टाक" बनाएं जो आगे फिर आकर हमारे काम आ सके । खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के सेक्रेटरी श्री शंकर महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि चीनी के बारे में शासन की कोई दूरगामी नीति नहीं है । मैं उनका एक उद्धरण सदन के सामने रखना चाहता हूं, यह अखबार की एक कतरन से है :

"Shri Shanker further added that the absence of a long term approach was mainly responsible for the ills of the industry. He observed that there had been a tendency to have a "crisis approach" to solve tbe problems as they arose and then to relax. This approach should be abandoned once for all."

यह कृषि खाद्य मन्त्रालय के सचिव महोदय का कहना है, मैं नहीं जानता व य बात किससे कह रहे हैं । खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय चीनी के सम्बन्ध में अभी तक कोई सन्तोषजनक नीति का विकास क्यों नहीं कर सका, इस विवाद में इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये । आज चीनी की कमी है, नगरों में चीनी का राशनिंग किया जा रहा है यद्यपि मन्त्री महोदय उसे राशनिंग नहीं क ते, रेगुलेशन कहते हैं । शब्दों के जाल से उपभोग भोक्ताओं की परेशानी दूर नहीं हो सकती । अनेक नगरों में बिना राशन कार्ड के चीनी नहीं मिलती और अनेक नगर ऐसे हैं ज ां जाली राशन कार्ड बनाए हुए हैं । जो सच्चा खरीदार है वह चीनी नहीं पा सकता और चीनी के व्यापारी शासन के साथ सांठगांठ करके चीनी को चोरबाजार में भेज रहे हैं ।

यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह संकट क्यों पैदा हुआ ? मन्त्री महोदय कहेंगे कि गन्ने की पैदावार कम हुई । लेकिन मैं जानना चाहता हूं गन्ने की पैदावार कम होने के लिये कौन उत्तरदायी है । सन् १९६०-६१ में जब गन्ने की पैदावार काफी हुई, चीनी की उपज बढ़ी और शासन को मौका था कि वह एक बफर स्टाक तैयार करता । सरकार ने अदूरदर्शिता से चीनी की पैदावार को कम करने के लिये कानून का सहारा लिया और चीनी मिलों से कहा गया कि वे पैदावार में १० फी सदी की कटौती कर दें । उस साल गन्ना किसानों के खेतों में खड़ा सूख गया । मैंने अपनी आंखों से देखा, गन्ना ईंधन की तरह आग में जलाया गया । नतीजा यह हुआ कि अगले वर्ष किसानों ने गन्ना कम बोया, उसका

परिणाम हमें यह दिखायी दे रहा है कि चीनी की पैदावार घटी है ।

दूसरी बात यह कही जाती है कि जो गन्ना पैदा हुआ वह खंडसारी और गुड़ के निर्माण में चला गया, चीनी के मिलों को काफी गन्ना नहीं मिला । यह बात सच है कि गन्ने का अभाव रहा । लेकिन क्या हमने सोचा कि गन्ना उत्पादक गुड़ और खंडसारी में गन्ना क्यों ले गए ? क्योंकि सरकार ने किसानों को गन्ने का उपयुक्त मूल्य नहीं दिया । गन्ना पैदा करने में किसान को कितनी लागत है, उसे गन्ना मिल के दरवाजे पर ले जाने में कितनी परेशानी होती है, शासन ने इसका विचार नहीं किया । अब अगर किसान के लिये गुड़ और खंडसारी में गन्ना बेचना लाभजनक है तो वह मिल में गन्ना क्यों ले जाएगा ? संसद् में इस तरफ से हम मांग करते रहे हैं कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाय लेकिन शासन ने गन्ना उत्पादकों को कोई प्रोत्सा न नहीं दिया । अब अगर गुड़ और खंडसारी बनाने वाले उन्हें अधिक दाम देते हैं तो किसान जरूर अपना गन्ना उनके पास बेचेंगे । आप कोई कानून बना कर किसानों का य अधिकार छीन नहीं सकते । वैसे मिल के क्षेत्र में खंडसारी तैयार करने पर कुछ रोक लगी हुई है और मिल मालिक मांग कर रहे हैं कि यह रोक बढ़ाई जाय । मैं इसके समर्थन में नहीं हूं । गांवों में जाकर गुड़ अथवा खंडसारी पर नियन्त्रण करना बड़ा मुश्किल है । म उन सरकारी कर्मचारियों के हाथ में ऐसा अधिकार नहीं दे सकते जिससे गन्ना पैदा करने वाले किसानों का उत्पीड़न हो । जिस भाव खंडसारी और गुड़ बिक रहे हैं उससे किसी को सन्देह नहीं होना चाहिये कि अगले साल भी जब गन्ने की नयी फसल आएगी तो गन्ना पैदा करने वालों को खंडसारी और गुड़ पैदा करने वाले ज्यादा दाम देंगे । गन्ने की पिराई मिल में शुरू होने से पहले ही गन्ना खंडसारी और गुड़ में चला जायगा ? शासन इसको किस तरह से रोक सकता है ? आप खंडसारी के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर रोक लगा सकते हैं लेकिन किसानों को अपना गन्ना अपनी इच्छा के अनुसार बेचने के अधिकार से यह शासन, जो किसानों के हित की रक्षा का दावा करता है, किस प्रकार वंचित कर सकता है ?

मैंने आपसे निवेदन किया कि पिछले वर्षों में शासन की नीति चीनी के बारे में बड़ी अस्थिर रही है । कभी कण्ट्रोल लगता है, कभी कण्ट्रोल हट जाता है, कभी मिल मालिकों की एक्साइज ड्यूटी में छट दी जाती है । फिर पैदावार बढ़ जाती है, फिर नियम बनाया जाता है, पैदावार कम करो । और जब पैदावार कम हो जाती है तो फिर कण्ट्रोल लगाया जाता है । यह स्थिति कब तक चलेगी । यह कह कर आप इस स्थिति को नहीं टाल सकते कि संकट दो महीने का है और यह टल जायेगा । मैं इस विवाद का इस बात के लिये उपयोग करना चाहता हूं कि शासन चीनी के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट शब्दों में प्रकट करे और गुड़ और खंडसारी का उस नीति में क्या स्थान होगा, इसका भी विवेचन किया जाना चाहिये ।

इस वर्ष चीनी की पैदावार कम हुई है, लेकिन मेरा आरोप है कि जो पैदावार हुई है उसका भी ठीक तौर से वितरण नहीं किया गया । इस प्रकार की शिकायतें आई हैं और उनकी जांच होनी चाहिये कि चीनी का कोटा देने में देरी की गई । इस बात की जांच ससद् की समिति कर सकती है, या कृषि मन्त्रालय एक उच्चाधिकार सम्पन्न कमेटी बनाए जो इस बात का पता लगाए कि क्या चीनी का कोटा रिलीज करने में देर हुई है और इस देर के लिये कौन जिम्मेदार है । उस दिन प्रश्नोत्तर काल में श्री टामस ने कहा कि जितनी चीनी हम पहले रिलीज करते थे उतनी कर रहे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है ।

अगर चीनी उपभोक्ताओं को दी जा रही है तो चीनी का संकट क्यों है ? या फिर वे स्वीकार कर लें कि उन्होंने जो चीनी पर नियंत्रण का आदेश १७ अप्रैल को जारी किया था उस आदेश के कारण चीनी का

[श्री ए० ब० वाजपेयी]

अभाव बढ़ा है, चोर बाजारी में वृद्धि हुई है । अभी तक नियंत्रण का अनुभव अच्छा नहीं है । जब जब चीनी पर नियंत्रण लागू किया गया चीनी की पैदावार घटी है और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी नहीं मिली । और जब जब सरकार ने नियंत्रण हटा दिया चीनी का उत्पादन बढ़ा और जब जब खुला बाजार रहा तब तब उपभोक्ताओं को कम मुश्किल का सामना करना पड़ा है । मैं कंट्रोल के सवाल को किसी राजनीतिक चश्मे से देखने का हामी नहीं हूं । कंट्रोल लागू होगा तब ही समाजवाद आयेगा और अगर हम ने कंट्रोल की व्यवस्था को हटा दिया तो समाजवाद आते आते रुक जायेगा, ऐसा जो विचार करते हैं, मेरा उन से बड़ा मतभेद है । केवल कंट्रोल लगाना ही काफी नहीं है, कंट्रोल लगाने के बाद जो समस्याएं पैदा होती हैं उनका भी विचार होना चाहिए । जो जरूरतमन्द हैं वे चीनी नहीं पाते हैं । गांवों में हम चीनी की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं । कार्ड बांटे गये हैं और एक कार्ड पर आधा किलो चीनी मिलती है और वह चीनी भी चोर बाजार में बेची जा रही है । क्या शासन, चीनी का वितरण राज्य का विषय है, यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है ? जब कभी चीनी के वितरण का प्रश्न उठाया जाता है तो माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि राज्य का विषय है । क्या राज्य सरकारें केन्द्र का आदेश नहीं मानती हैं जबकि राज्यों में और केन्द्र में एक ही दल का शासन है ? जब आज यह स्थिति है तब केन्द्र और प्रान्तों में भिन्न भिन्न दलों का शासन होगा तो क्या स्थिति होगी ? राज्य का विषय है, इसलिए शासन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है । मेरा निवेदन है कि सरकार इस सदन को विश्वास में लेकर बतलाये कि १९६१–६२ में चीनी की पैदावार में जो १० फीसदी की कटौती की उसका कितना असर हुआ और यह भी बताया जाय कि बाद में चीनी की पैदावार का जो लक्ष्य रखा गया है वह कैसे पूरा होगा ? अब तो कहा जा रहा है कि हम अगले साल ३४ लाख टन चीनी पैदा करेंगे और इस साल २२ लाख टन चीनी पैदा हुई है । इतनी वृद्धि चीनी की पैदावार में कैसे होगी ? इस सम्बन्ध में शासन की क्या योजना है और सरकार किसानों को क्या सुविधा देने जा रही है ? मेरा निवेदन है कि सरकार को चीनी के संबंध में अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए ।

चीनी के निर्माण में चीनी उत्पादक, निर्माता, उपभोक्ता और शासन सब हिस्सेदार हैं । चीनी केवल मिलों में ही तैयार नहीं होती, चीनी खेतों में उगाई जाती है गन्ने के रूप में । गन्ना पैदा करने वाले किसान को उस की मेहनत का पूरा पैसा मिलना चाहिए । मेरा सुझाव है कि गन्ने के दाम कम से कम २ रुपया मन होने चाहियें । यह प्रस्ताव मैंने लोक-सभा में रखा था तब ठुकरा दिया गया । लेकिन मुझे विश्वास है कि ठोकर खा कर स्वयं सरकार इस परिणाम पर पहुंचेगी कि जब तक गन्ना पैदा करने वाले किसानों को मिल में गन्ना ले जाने में अधिक फायदा नहीं होगा तब तक गुड़ और खन्डसारी निर्माताओं के हाथों गन्ने का बेचा जाना रोका नहीं जा सकता है । एक बात मैं यहां पर कह दूं कि रिकवरी के आधार पर सरकार गन्ने के दाम तय करने जा रही है । इसका परिणाम यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने के दाम में कमी हो गई है । जहां गन्ने के लिए पर्याप्त पानी नहीं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जहां की सरकार ने पिछले १५ सालों से गन्ने की किस्म का विकास करने में, उस में शर्करा तत्व को बढ़ाने में ठोस कदम नहीं उठाया, इसलिए वहां के किसान इस रिकवरी फार्मूला से घाटे में रहे हैं । फिर भी हम चाहते हैं कि किसान अधिक गन्ना बोये लेकिन उस के लिए शासन की तरफ से सहयोग मिलना चाहिये । उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना पैदा करने वाले

लाखों किसान उन सुविधाओं से वंचित हैं जो शासन की ओर से दी जानी हैं। ट्यूब वैल नहीं हैं, ट्यूब वैल अगर हैं तो चलते नहीं हैं। गन्ना पैदा करने वाले किसान उनका पूरा फायदा नहीं उठा सकते। गन्ने की किस्म का विकास करने के लिए केन सेंसेस लिया जाता है। आज सवेरे प्रश्नोत्तर काल में, श्री टामस ने यह बात बतलाई कि अधिकतर सरकारें केन सेस का उपयोग गन्ने के विकास में नहीं करतीं और इसके द्वारा जितना रेवन्यू मिलता है उस को खजाने में जमा कर देती हैं जिसकी वजह से किसानों को सुविधा नहीं मिलती है। अगर संविधान केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में निर्देश देने से रोकता है तो भी मेरा निवेदन है अनौपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों पर इस बात के लिए दबाव डालना चाहिये कि "केन सेस" से प्राप्त होने वाला रुपया वह गन्ना क्षेत्र में खर्च करें, सिचाई की सुविधा बढ़ायें, मिलों के आस पास सड़कों का जाल फैलायें और नालों पर पुलिया बनायें जिस से किसान आसानी से गन्ना लादकर ले जा सकें। यदि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में अपने दायित्व का परिपालन नहीं करतीं तो केन्द्रीय सरकार कब तक संविधान की ओट लेती रहेगी ?

चीनी केवल उत्तर प्रदेश और बिहार का ही उद्योग नहीं है। हमारे औद्योगिक संस्थानों में चीनी उद्योग का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हम आज विदेशों को चीनी भेज रहे हैं और उस से हम विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। विदेशी बाजार में हमारी साख जम रही है और इस समय जब कि विदेशी बाजार में, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो हमें विदेशी बाजारों में भी अपने पांव जमाने की जरूरत है। लेकिन प्रान्तीय सरकारें इस सम्बन्ध में जो रवैया अपना रही हैं वह चीनी उत्पादन को कम करने वाला है। यह रवैया बदलना चाहिये।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि चीनी मिलों को भी उत्पादन वृद्धि के लिए कुछ सुविधाएं दी जायें। अगर पिछले साल की तुलना में अधिक पैदावार करती हैं तो जितना उत्पादन वे इस वर्ष अधिक करें, उस में उन्हें एक्साइज ड्यूटी पर छूट देने का विचार किया जा सकता है।

तीसरी बात, चीनी के दाम निर्धारित करते समय हम सारे उत्तरी भारत का एक जोन न बनायें। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनकी भिन्नता को ध्यान में रखें। इन क्षेत्रों में चीनी के उत्पादन की लागत अलग है। अलग अलग जोन बना कर के चीनी के मूल्यों का निर्धारण होना चाहिये। मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय को ज्ञात है या नहीं कि चीनी के मिल मालिक यह आरोप लगा रहे हैं कि कृषि तथा खाद्य मंत्री दक्षिण के हैं और उनके सहकारी भी दक्षिण के हैं, इसलिये उत्तर की मिलों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि यह आरोप कहां तक ठीक है, लेकिन यह आरोप लगाया जाय यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। शासन मूल्यों का निर्धारण करते समय इस बात का विचार करे कि उत्तर और दक्षिण की भावना पैदा न हो और उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के चीनी के निर्माता भी प्रतियोगिता में ठहर सकें।

मिलों को यह भी आदेश दिया जाना चाहिये कि अक्तूबर से गन्ने की पेराई शुरू कर दें। उस समय गन्ने में रस कम होगा, यह बात ठीक है, लेकिन अगर अक्तूबर में पेराई शुरू नहीं हुई तो गन्ना गुड़ और खंडसारी की तरफ जाने लगेगा और फिर उसे रोका नहीं जा सकता। अक्तूबर के अन्त में या नवम्बर के प्रारम्भ में गन्ने की पेराई होनी चाहिये। मिलों से यह भी कहा जाय कि वे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार चीनी का उत्पादन करें।

[श्री ए० बा० वाजपेयी]

शासन की तरफ से एक कमेटी बनी थी, गुंडूराव कमेटी । उस ने कुछ सिफारिशें की हैं । उन सिफारिशों को अभी पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है । उन को अमल में लाना जरूरी है ।

सब से बड़ी बात यह है कि आंशिक विनियंत्रण होना चाहिये । चीनी से अगर नियंत्रण हटा दिया जाय और चीनी खुले में मिलने लगे तो थोड़े दिनों में कठिनाई दूर हो जायेगी । चीनी की खपत बढ़ रही है और उसका इलाज उत्पादन बढ़ाना है, नियंत्रण करना नहीं । कोई चीज कम हो तो नियंत्रण की आवश्यकता मैं समझ सकता हूं, लेकिन नियंत्रण प्रभावी नहीं हो पाता । नियंत्रण गांव वालों का विचार नहीं करता । नियंत्रण चोरबाजारी को प्रोत्साहन देता है । अभी तक, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, चीनी के सम्बन्ध में नियंत्रण का अनुभव अच्छा नहीं है और आज भी जिन नगरों में नियंत्रण लगा है वहां लोग आसानी से चीनी नहीं पा रहे हैं ।

एक बड़ी विचित्र बात है कि दिल्ली में चीनी का कोई संकट नहीं है । दिल्ली की जनता चीनी के लिये नहीं चिल्ला रही है । शासन ने जान बूझ कर यह स्थिति पैदा की है । दिल्ली के लिये जो चीनी दी गई है वह यहां की जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज्यादा है । इसलिये यहां चीनी का कोई संकट नहीं है । मगर उत्तर प्रदेश में और पंजाब में चीनी का संकट है । मैं यह नहीं चाहता कि दिल्ली में भी चीनी का संकट पैदा किया जाय, लेकिन केवल दिल्ली पर कृपा करके शासन संकट को कम करके नहीं दिखा सकता । आवश्यकता इस बात की है कि इस चीनी के अभाव के लिये शासन अपनी जिम्मेदारी समझे और जैसा कि मैं ने प्रारम्भ में कहा कि संसद के सदस्यों की कमेटी बनाई जाय तो इस बात का पता लगाये कि इस वर्ष चीनी का अभाव क्यों हुआ और उसके लिये कौन जिम्मेदार है और भविष्य के लिये ऐसी सिफारिशें करे जिससे ऐसी परिस्थिति की पुनरावृत्ति न हो ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन के विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

SHRI N. SRI RAMA REDDY (Mysore): Madam Deputy Chairman, this really is a matter of great urgency and therefore, it is in the fitness of things that we should discuss this subject in this House, namely, the question of the shortage of sugar that is being felt at present in the country. Madam, the occurrence of shortages periodically in this country is not a new thing. One at least in the post-independent period we have had. In 1948-49 we had shortage and again in 1953-54 we had a very severe shortage when we imported into this country as much as 7.29 lakh tons of sugar. In 1954-55 also we had to import about 5.74 lakh tons and 1955-56 was the last year when we imported sugar to the extent of 60,000 tons. Thereafter the sugar position in the country improved and we were very well placed in that year. Next year, i.e., 1957-58 we exported 47,000 tons of sugar and that was followed in 1958-59 by an export of 32,000 tons. Thereafter, I do not have the figures to show whether we exported anything at all. Anyway, it is now proposed to export about 5.4 lakh tons of sugar from out of the country this year. This is the position with regard to the occurrence of shortage of sugar in this country.

Madarn, I feel that the position is mainly one of production of sugarcane in this country. Sugarcane if being produced mainly—more thaa 50 per cent of the cane—in Uttar Pradesh and to a certain extent comes Bihar next. Maharashtra also occupies a very important place. The sugarcane produced in this country is iminly used for three purposes. *Gur*

or *jagg&ry* as we call it, is produced from sugarcane. Then *Khandsari* sugar is also produced from it, as a cottage industry, and on a factory scale sugar is being produced. Nearly 30 per cent, of the sugarcane produced in the country is going for the manufacture of white sugar whereas 55 per cent, of it is being used for the making of *Khandsari* and *jaggery* or *Gur* and the rest 15 per cent is being used for chewing purposes, or for the preparation of sweets and things of that sort. This is how the total sugarcane that is produced hi the country is being allocated.

Our position with regard to the production of sugarcane was quite satisfactory, at any rate from the year 1957-58 when the acreage was also increased. Nearly 50 lakh acres were put under sugarcane in 1957-58 and it gradually rose and in 1960-61 it was 57 lakhs and in the year 1960-61 our production of white sugar was a peak production. We produced nearly 30 lakh tons. That was the highest ever produced in the country and therefore, we felt very happy and we felt that the question of sugar production in the country Was once and for ali solved. Unfortunately, immediately after, in the following year, though the area under cane was increased to 59 lakh acres, the production fell to nearly 27 lakh tons of sugar. In spite of the fact that during the year 1961-62 there was a fall in the production of sugar, a particular advic$_e$ was given. The year 1961-62 was a very crucial year, according to my reading, with regard to sugar production in the country. I do not know if the Food and Agriculture Ministry was correct or not, but what happened was that an advice was sent out that people must reduce sugarcane production by at least 50 per cent. That was the advice given to the States. This, according to me, wa$_s$ a *very* unfortunate advice. In spite of the fact that from 30 lakh tons the production of sugar had fallen to 27 lakh tons, an advice of this kind was sent out from the Food and Agriculture Ministry.

I recall an incident which happened in the U.S.A. some tim$_e$ ago. It was the year o'f peak production 3 P.M. of potatoes and the farmers were worried because they were not getting any sellers for their produce. Government went to their rescue not by asking them to curtail production but by asking them to produce more and promising to take up all the stock to be used as best as they thought fit. If such a policy had been followed here, we would not have had to face the second crisis with regard to sugar production, Unfortunately, unmindful of the reduction in sugar production the year 1961-62, this advice was sent round and unfortunately those farmers in U.P. and West Bihar who could not sel] their cane were forced to convert it into *gur* or *khandsari.* The enthusiasm of the farmers was very much chilled in the year 1961-62 with the result that next year the total acreage came down from 59 o$_r$ 60 lakh acres to 52 lakh acres, the fall in the area being as great as eight Iakh acres. The immediate result of this was a shortfall in the production of sugarcane. The reduction in production came inevitably partly because of this advice and partly on account of other conditions and the production in the year 1962-63 came to 21.5 lakh tons, a fall of ten lakhs or one million tons. This has had a disastrous effect on our sugar position. Of course, in 1962-63 our consumption rose to 26 lakh tons whereas the production was of the order of 21.5 Iakh tons. Fortunately, we could depend upon the buffer stock that was there of the previous year's production which was said to be of the order of about a million tons. Thus we could get over the difficulties in 1962-63. I have here the answers given by the hon. Deputy Minister last year to question raised by my hon. friend, Mr. Vajpayee. He asked,

> ". . . whether it is a fact that the farmers are put to financial loss by belated crushing of sugarcane."

[Shri N. Sri Rama Reddy.] and the answer wa*

"Yes."

The further question was:

"If so, what is the policy of the Government in this matter?"

and the reply was:

"The policy of the Government in this matter is to make efforts to see that all available cane was crushed."

This was the policy of the Government only a year back and so soon after, in the year 1963, the twenty factories were advised by the Ministry to go On crushing the cane in order to give facilities to the farmers, and now this sort of advice goes round. In reply to a supplementary question I had Put, the hon. Deputy Minister was pleased to say:

"Ths main problem is in the States of U.P. and Bihar."

In North Bihar, there were three factories, in Eastern U.P. four arid ten in Western U.P. This was the specific advice given by the Ministry of Food and Agriculture to keep thefactories going in order to crush all the cane that was made available to the factories. What is the position a year later? I need not refer to the facts and figures but the story goes that the number of factories has increased from 160 to 180, nearly twenty factories have come up. These factories are not getting the cane necessary to crush. Here I entirely agree with my hon. friend, Mr. Vajpayee, when he says that a rethinking i_s an absolute necessity with regard to the policies that we are putting forward. We cannot get away by saying that this is accounted for by the increase in population and things like that. Our consumption i_s going to be probably 28 lakh tons. The prospects for 1963-64 are also not good. If I may here divulge a secret, probably it is no longer a secret, the sugar stock available with us is hardly four lakh tons, a quantity equal to two months consumption, This, it is said, wiH last us. till the end of October at the present controlled rate of distribution. Here,. I am really to congratulate the Food and Agriculture Ministry in that it introduced control as early as April. If it had not been so, all the sugar would have disappeared by now and we would have been in a great mess. Therefore, I congratulate the Ministry. Though they had committed a blunder in th_e previous year, they have attempted to correct it by introducing controlled distribution. To this extent, the forethought of the-Ministry is really to be appreciated by this House. The position now is none too less dangerous because you can have thi_s arrangement only till the end of October when even the buffer stock would be exhausted. Unfortunately, this is off-season; there is no crushing and no sugar could be produced in the country. Most of the sugarcane comes from U.P. and North Bihar and in U.P. particularly there are sixty or sBventy factories. All these factories will start working from th_e middle of November. This meam that sugar will be available only towards the end of November. In the meanwhile, all our sugar stock will have been exhausted by October and there is a gap of one month. This is a very serious matter, according to me with regard to the sugar position in the country. I do not know whether hon. Minister for Food and Agriculture hag any plans for making up this shortage.

Madam, I was not able to very thoroughly follow my hon. friend, Mr. Vajpayee, when he was discussing the subject in Hindi but from what little I could make out, he wanted the controls to go.

SHRI A. B. VAJPAYEE: Madam Deputy Chairman, I wanted partial decontrol.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: Even partial de-control will introduce problems in the short supply position we are facing today. Therefore, the

policy of the Government is very correct. After all, we must also ad-Tise the country about our reaction in times of crisis.

DR. A. SUBBA RAO (Kerala): Is the present policy correct or was the old policy wrong? What is it?

SHRI N. SRI RAMA REDDY; I have said enough Madarn, I recall with a certain amount of deep affection an incident that I faced in Denmark in the year 1951, when I had gone there.

I was invited to a farmer's house to take tea and he told me, 'You see, in our country sugar is controlled. We are allowed only one spoon each but you are an honoured guest and guests are allowed two spoons. So you can have two spoons and we will have one each.' All the members of that household served themselves only with one spoon each of sugar and they asked me to serve myself with two spoons. Is it not a great national trait? Should we go on condemning the Ministry, the policy and the country and everything when we are facing a crisis? The crisis anyway has come whatever may be the reasons fo$_r$ it but is it not our duty to co-operate with the Government and everybody concerned to face the crisis boldly and come out of it successfully? After all that much of severe controls' are not here today. Therefore, I say even partial decontrol should not be there. Partial control should also be not there; it must be complete control till we get over the difficult period particularly becaue I am afraid November will be a very bad month.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have taken 15 minutes and there are many speakers. Just as you want to deny yourself sugar, you must also b$_e$ brief.

SHRI A. B. VAJPAYEE: He did not deny himself; he took two spoons.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: So, Madarn, things are not very bad. More factories are coming up in the South; I am very happy from the records to find that the Ministry is encouraging greater number of factories in the South. Certainly this is as it should be because what can be produced in two acres in the North can be produced in one acre in the South.

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh): That is not the case. You are quite wrong there.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: It is quite right. Anyway let us wait for the Minister to give the figures. It is a good thing that they are encouraging a greater number of factories to come up in the South and I suggest , that a greater number of factories should be allowed in Mysore particularly because I come from Mysore.

Now, I have got a few remedies.

(Interruptions.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Be mindful of the time and please wind-up.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: With regard to the question of remedies, I would like to know if the 5.4 lakh tons of sugar have already been exported and if it is not exported, is it not possible to retain two lakh tons for getting over the crisis in the month of November? If that is done and if you advise the 'factories to start crushing early in October itself, we can get over the crisis; otherwise we will be in great danger. Madam, production is the main thing. I have toured in U.P. and I would like to share with the Agricultural Minister one fact, which came to my notice. In U.P. the agricultural practices followed are so medieval and so old, the irrigation given so scanty that I think that there is greater possibility immediately next year to improve sugar production to 30 lakh tons or even 33 lakh tons as targeted. It is quite possible but the only thing that has got to be done is to give sufficient irrigation, I found in U.P., in Gorakhpur and other places which I visited last summer, that they are giving irrigation onc$_0$ in 40 days.

[Shri N. Sri Rama Reddy.] Fhis is a barbarous way of producing cane. In the South, Madarn, irrigation is given during summer months «very ten days. That has got to be given. But here in spite of the fact that there is water they do not do it.

SHRI ARJUN ARORA: In spite of that the crop in Mysore takes eighteen months to ripen while the crop in U.P, takes only nine months.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: My hon. friend is wrong there. It takes only ten months in Mysore and in U.P. it takes nine months So there is not much difference. Therefore I say that the agricultural practices and irrigation methods followed in U.P. and Bihar where fortunately or unfortunately there is greater cane grown should be given proper attention.

Madarn, with these remarks I conclude.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Kerala): Madam Deputy Chairman, the present sugar shortage is the creation of the Government as a result of the mistaken policies they were consistently following. My hon. friend, Mr. Vajpayee and also my hon. friend, Shri Sri Rama Reddy, touched on some of the points. Now, I am not going to enter into the quarrel whether U.P. produces more or Mysore produces more sugar but as it is, U.P., Bihar and Punjab are the main producers of sugar. In the matter of giving encouragement to the peasants for growing more cane, the policy followed by Government was one which actually discouraged them. Because as pointed out by my hon. friend here, both the Bihar Government and the U.P. Government wanted an increase in the price o'f sugarcane but the Central Government turned it down. The- result was not one of the encouragement but it discouraged in a big way the production of sugarcane.

Secondly, it was mentioned here that proper irrigation facilities were not given. And as far as the price •oi the cane is concerned, a new device of fixing the price-of the cane was put forward by the millowners; that is to say, the price was to be linked up with the sucrose content which means that as far as the price of the cane was concerned the deciding authority was the millowner. So all these things instead of encouraging more production actually discouraged it.

Thirdly, the Ministry was very complacent about the sugar position. I remember some time ago when the question of exporting sugar was discussed in this House the Food Minister was very eloquently arguing that even by giving subsidies we have to encourage export of sugar, otherwise the entire industry will be ruined. So it is this complacent attitude on the part of the Government that has now led to this present crisis. The contention at that time was that we were producing more. I think it was in 1960-61 that we had our peak production of 30 lakh tons and we were then very anxious to export sugar instead of trying to build up a buffer stock. Now in certain other sectors the Food Ministry stress the importance of building up a buffer stock to control prices, etc. Why is it that they failed to understand that if there is some over-production in one year, that opportunity should be utilised tc build up a buffer stock, so that we may not suffer from shortage? That idea did not strike them. Not only that. At that time, I am afraid more than any other, they were carried away by political considerations. It was at a time when the U.S.A in order to put pressure on the Cubans refused to buy from them and they were seeking new places from which they could buy sugar. So, in order to oblige the U.S.A. in their endeavour to defeat the Cubans, we thought we should export sugar. That is why I said it was political considerations rather than other considerations that weighed with the Government at tnat time. Now, we are in a mess. Here the other day, while the Food Minister was replying to a question, he said that this time we are short of more than two lakh tons as compared to

the time previous to the control. Even on a previous occasion we had to introduce control because there was not enough sugar to be distribut-[1] ed. Actually, the shortage is much more and 'from the answer that he gave the other day the stock in the hands of the Government is only 4 lakh tons or so. So, we are faced "with a very serious situation and this can be got over, even with difficulty, only if the Government enforces stricter control. I could not understand the argument of my hon. friend, Shri Vajpayee, when he said that what is needed is a partial decontrol. At a time when there is a shortage and we have no plans of getting over it, how is a partial decontrol going to help us? That will only further worsen the situation and as such the Government should not think in such terms. They should think in terms of enforcing stricter control and of a more equitahle distribution.

Now, there ar$_e$ many complaints about the way in which sugar is being distributed. During the short time at my disposal I do not want to go into all those th'ngs. What I suggest is this. The Minister himself said the other day that each State is following its own policy on control, that is to say, they have their own method of distribution. We have received complaints 'from many States that the policy they are following is faulty. A better control and a more equitable method of distribution should "be the "basic idea on which the Government should try to get over the present crisis.

Secondly, the Government should give up the wrong policies they were following. A new policy of encouraging production both at the sugarcane level and sugar level should he evolved. Now, what happens is this. If a proper price for sugar is not assured, instead of sugar, gur and some other things are produced from sugarcane. So, the Government has to pursue a proper policy by which the cane-growers get the benefit. They should also get other encouragements :Eor •432 RSD—5.

better production. In that way, the Government should face the problem. This sugar crisis is something which we can avoid because there is every possibility of producing enough sugar for our use. And if we properly plan, we will be able to produce for export also. In such circumstances, to burden the country with such a shortage, is really an admission o'f the failure of their policy and I hope the Government will depart from th$_e$ policy they were pursuing.

श्री सीताराम जयपुरिया (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, यह बहुत दुःख की बात है कि हम लोगों को चीनी की इस कमी के ऊपर आज बहस करनी पड़ रही है । दरअसल यह बात पिछले ६-७ महीने से उठी थी लेकिन माननीय मंत्री जी हमेशा यह कहते रहे कि चीनी का स्टाक काफी है, कोई चिन्ता की बात नहीं और इसके लिए चीनी का जो पर्याप्त इन्तजाम करना है वह किया जायेगा । लेकिन अफसोस की बात है कि वह जितनी बातें कही गई थीं वे सही नहीं निकलीं । और जो कई कारण थे जिनके बारे में हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने बताया और खासतौर पर प्रस्तावक महोदय श्री बाजपेयी जी ने क ा, वे तो हैं ही, एकरेज में कमी हुई, उत्पादन में कमी हुई, कटौती भी की गई, लेकिन इसके अलावा मैं समझता हू जो कंट्रोल किया गया वह सब से बड़ा कारण है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा शार्टेज और कमी महसूस होती है । जहां तक १० प्रतिशत कटौती का प्रश्न है, मेरा अपना विचार है कि वह एक ऐसा समय था जब कटौती करना एक प्रकार से आवश्यक सा था । परन्तु उस समय एक बात जरूर सोचने की थी कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, रीजन हैं, जिनमें हमेशा हर साल एक ही मिकदार में गन्ने का उत्पादन नहीं होता बल्कि प्रकृति पर बहुत कुछ निर्भर करना पड़ता है । अगर एक साल गन्ना अधिक पैदा हो गया तो सरकार को यह सोचना चाहिये आगामी फ़सल में क्या होगा क्योंकि नेचर

[श्री सीताराम जयपुरिया]

हमेशा साथ नहीं देता है और समस्या ऐसी आ जायेगी कि वहां गन्ने की कमी हो जायेगी। उस हालत में जब कि आज जो बफर स्टाक ५ लाख टन करने की बात है जिसके लिए मैंने माननीय मंत्री जी से आज एक प्रश्न भी पूछा था और उन्होंने उसका उत्तर यह दिया कि अभी यह मामला फौर्मेशन स्टेज में है

and it will take years before that can be done. If the same situation could have been visualised at that time, then probably the situation would have been a little different.

अब उसमें सब से बड़ी दूसरी बात यह है कि जो कंट्रोल भी किया गया उस कंट्रोल का नतीजा क्या हुआ ? आप सोचिये कि १७ अप्रैल को कंट्रोल के वक्त गुड़ का दाम २२ रुपया मन रहा था और खन्डसारी के दाम ४० रुपया मन थे। आज गुड़ का भाव ४० रुपया मन है और खंडसारी का भाव ६५ रुपया मन है और चीनी के भाव जो कंट्रोल के वक्त थे, जिसका कारण गवर्नमेंट ने बताया कि दाम इतने बढ़ गये जिसकी वजह से हमें कंट्रोल करना पड़ रहा है। वह मूल्य उस समय ११५ रुपया क्विन्टल था यानी १.१५ नया पैसा किलो। गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल के दाम फिक्स किये वह १११.५० रुपया था। मैं अदब से पूछता हूं कि जब १११.५० रुपया सरकार ने फिक्स किया तो उस समय ११५ रुपये दाम थे, तो इतने दाम क्यों चढ़ गये थे जिसकी वजह से कंट्रोल करना पड़ा। कंट्रोल करने में जितनी परेशानियां और जितना चरित्र में गिरावट हमेशा इसकी वजह से होती है उस को हर एक ने मंजूर किया है। शायद ही कोई पार्टी का नेता ऐसा होगा जो यह महसूस न करता हो कि जितनी गिरावट हमारे चरित्र में कंट्रोल की वजह से होती है उतनी किसी चीज से नहीं होती है। फिर भी वह कंट्रोल किया गया और कंट्रोल करके आज हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गये। हमने कंट्रोल कर दिया और हम क्या कर सकते हैं। नतीजा उसका आज यह है कि बाजार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर १५५ रुपये से लेकर १६५ रुपये के भाव तक से कम में शक्कर मिले यानी एक तरह से भाव १ रु० ६५ नये पैसे पर किलो हुआ। यही नहीं बल्कि यहां तक है कि उदयपुर में यह जानकर आप को आश्चर्य होगा, जहां पर शुगर फैक्ट्री भी है, इस समय का भाव २८५ रुपये क्विंटल है यानी २ रु० ८५ नये पैसे पर किलो।

If that is the result of control and if we feel satisfied that we have done-our duty by introduction of control, I beg to submit that we are grievously mistaken, and we are not doing the-part that we are supposed to doi *(Interruption).* The question is that ia Delhi, as the mover said earlier, there is plenty of sugar. Undoubtedly even today if any one goes for the release of a quota of sugar for Delhi,, he can get 2000 bags. But what i* happening? We do realise that there-is no shortage in Delhi. But newspaper reports will prove* and that *is*-a fact too, that from Delhi Shadara< a good quantity of sugar is being: smuggled into Ghaziabad and other neighbouring areas. Is that the way of implementing controls? Even at Gorakhpur which is primarily a sugar-producing area, the price of sugar is-today not less than Ks. 165.

Mr. Vajpayee earlier moved and? suggested for partial decontrol. If I say that complete decontrol is the-only solution, I do hope I will not be misunderstood. Why I say that, Madam Deputy Chairman, is not because of many reasons. I am not one of those who is against khandsari,, but I do submit and submit very humbly that if the price of khandsari is going to remain at Rs. 65 a maund, which means more than Rs. 1'50 per seer, and the cost of production of sugar is definitely very much more than khandsari, it will amount to» nothing else but this: "Thus far shall thou go and no further",, as Nepoleoa

said. No wishful thinking no pious hopes and no unimaginative suggestions will ever solve the problem of sugar. What my friend, Mr. Sri Rama Reddy, said is undoubtedly true that production is a solution. But how that production is going to be achieved? Shri Vajpayee is absolutely correct that if the price of khandsari is high, there is no reason why a farmer should sell his sugarcane to the mills at a lower price. He also suggested that crushing should be started in October. I for one do feel that in order that the sugarcane may not be diverted to gur and khandsari early starting is necessary. But I also submit that the sucrose content of the sugarcane will be much less. If gur and khandsari are given this additional facility of crushing early, even then the country will lose a very good quantity of sugar which could be available to us at the end of the season. I do not suggest that gur and khandsari should be dealt with in a manner that they may not exist, but it is certainly necessary that certain effective checks are introduced.

DR. A. SUBBA RAO: He wants control there.

SHRI SITARAM JAIPURIA: I am aot suggesting control there Kindly hear me before you pass comments. I am sure you will be convinced of the arguments. The point is this. I say that licensing of gur and khandsari factory should be there, the sugarcane should be sold to them through the co-operative societies as it is being sold to the industry. The minimum price of sugarcane should be fixed for them also as in the case of sugar factories. I do know that in the early stages when a farmer is interested to sell his sugarcane and if the sugar mill has not started, the farmer naturally has to go to the gur and khandsari manufacturers, and many times before the mill season closes as late as March or April gur and khandsari manufacturers are in % position to buy at a low rate. If a minimum price is fixed, not only will the farmer be benefited but it will also ensure the availability of sugarcane to the sugar industry. The future of the sugar mill industry cannot in any way be ever separated from that of the farmer. High price of sugarcane is undoubtedly a solution for increased production. I do also realise the necessity of incentives that are proposed to be given and Mr. Patil said that unprecedented incentives would be announced. I would suggest that it should not take a very long lime to take a decision on this s-ore. But here again incentives are not going to solve the problem. The total cane production this year is 21 lakh tons, and when incentives were given previously, it was only 41 lakh tons additional production. I would ask on what basis the Government of India now think that our production will be to the tune of 33 lakh tons. To me it appears to be a figure which is absolutely out of tune with reality. Even last year the Government was estimating that the total production of sugar would be 28 lakh tons. And even till the end of February, when most of the factories were closed, the Government continued to say that whatever might happen, it would not be less than 25 lakh tons. Ultimately it came to 21 lakh tons. It is not jugglery of statistics which is going to help the Government. I remember that when a patient went to a doctor and said: "Doctor, what do you think of my disease? Do you think there is a chance of surviving?" The doctor said: "Statistics show that nine persons out of ten die of the disease you have. I have treated nine and they are dead. You are the tenth, you are bound to survive." After all statistics are statistics. When the fellow again went to the d.-ctor and said; "Doctor, your diagnosis of my disease is quite different from that *ot* the other doctors, the doctor said: "Yes, I know. I know, but post mortem will prove that I was right." I do hope that in the matter of sugar, necessity of post mortem will not arise and we will not have to judge who was right and who was wrong.

[Shri Sitaram Jaipuria.] The simple fact is, if you introduce controls, it should be the moral duty of the Government to ensure that all for shortage of cane do get their due share of quota. One of the reasons for shortage of cane, Madam, is that the cane cess money is not being fully and properly spent. On that this morning there was a lot of discussion. I would very humbly suggest that if the Central Government feel having utterly failed in directing the State Governments to ensure that that money is ^pent on cane development and research, it will be better if the cane cess is absolutely abolished and instead of that a development cess is imposed and that is placed entirely at the disposal of the Central Government so that they can ensure that cane research and development are done. That may be one of the acts by which the Government may be sure of having done a part of their duty.

Anomer factor is, the ration of sugar is being given on the basis of population and not on the basis of consumption. Though there is rationing in urban areas, in rural areas there is no rationing, and they have to buy sugar at high prices. The parity prices between gur and khandsari and sugar will have to be maintained whether we like it or not, and unless and until a practical formula is found out by the Government to ensure that the prices of all these three commodities remain in a certain proportion, I must say that in spite of all the efforts that the Government might like to make, it is going to fail, and there is no chance at all for improvement of the sugar position I most humbly suggest that this is such an important matter which involves every citizen, and unless and until the Government takes practical steps to ensure that sugar is available to every one, controls will not help. Decontrol might mean higher prices for the time being, but prices will go down. Prices of gur and khandsari will also go down. Today on paper we get it at Rs. Ill per quintal, tne real marketing is at Rs. 165. You will find that at least a good percentage of that sugar is going off the proper market in a bad way. I submit that if you calculate that, it is Rs. 5 crores every month that the consumer is losing and that money is going to such pockets as it will never be possible to be found out. In U.P. I know—and I do think that is the case in most of the other States—that 95 per cent, of the sugar retailers, who have been appointed for the distribution of sugar in the different towns today, are persons who are influential either in one way or the other; in a political manner or in some other manner they are influential people. They are not the normal trade personnel who have been living on this so far. This is one thing the Government should look into also.

श्री शील भद्र याजी (बिहार): माननीय डिप्टी चेयरमैन महोदया, अभी चीनी का संकट है इसमें कोई दो रायें नहीं हैं । चीनी का उत्पादन गत वर्ष क्यों घटा और अभी क्या परिस्थिति है इस पर हमारे वाजपेयीजी ने अच्छी अच्छी राय दी है और मैं समझता हूं कि जब तक गन्ने की कीमत दो रुपये मन नहीं कर दी जाती है तब तक जो गन्ने के उत्पादक हैं उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । इस बार जो संकट आया तो किसानों में एक तरह से गन्ना उत्पादन न करने की मनोभावना आ रही है और इसका सारा श्रेय जो शुगर इंडस्ट्री के मालिक हैं उनको है । एक एक शुगर फैक्ट्री में किसानों का दस दस या बारह बारह लाख रुपया बाकी है और किसान यह समझते हैं कि वह साल भर पैदा करते हैं और पैदा करने के बाद गाड़ी परलाद कर ले जाते हैं लेकिन तब भी उनको उसकी कीमत नहीं मिलती है । इसके लिये सरकार भी मालिकों को मजबूर नहीं करती है । इस वजह से किसानों में एक तरह से क्षोभ पैदा हो गया है, क्रोध हो गया हैऔर नफरत हो गई है और वह गन्ने की खेती नहीं करना चाहते हैं हालांकि गन्ने में उन्हें फायदा होता है—जो सरकार ने एक रुपया बारह आने मन का

दाम रखा है उसमें भी फायदा होता है फिर भी किसान इसे पैदा नहीं करना चाहते हैं । तो उनको अपना दाम न मिलने की वजह से बड़ी दिक्कत आती है इसलिये जो बड़ी बड़ी शुगर फेक्ट्रियों के मालिक हैं उनको इसके लिये सरकार मजबूर करे । मेरी तो राय यह भी है कि शुगर इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, शुगर का हिंदुस्तान में भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है और फारेन एक्सचेंज के लिये इसको हम बाहर भी भेजते हैं, इसलिये अगर शुगर इंडस्ट्री के मालिक मनमाने ढंग से लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं तो सारी शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया जाय, इसका राष्ट्रीयकरण किया जाय ताकि किसानों को वक्त पर गन्ने की उचित कीमत भी मिले और उनको गन्ने का उत्पादन करने का प्रोत्साहन भी मिले । हमारे सूबे में, खास करके हमारे जिले में, गन्ने में एक बार भी पानी नहीं दिया जाता है तो भी गन्ना अच्छा होता है लेकिन पंजाब में जहां दस पानी या बारह पानी देते हैं और महाराष्ट्र में जहां वराइटी भी अच्छी है और इरिगेशन के लिये भी इन्तजाम है, वहां रिकवरी बहुत अच्छी होती है और हमारे सूबे में भी जो खेत नहर के किनारे पड़ते हैं वहां गन्ना ज्यादा उत्पन्न होता है और उसकी रिकवरी भी अच्छी होती है लेकिन सिंचाई का प्रबन्ध न होने की वजह से वहां ४० फेक्ट्रियों में से १० फेक्ट्रियों के करीब चुपचाप बैठ गई हैं और इस वजह से भी काफी कठिनाई है । दिक्कत यह है कि किसान मेहनत भी करते हैं, कुएं से पानी भी लाकर देते हैं फिर भी उनको वक्त पर कीमत नहीं मिलती है और इसकी वजह से उनको अगले साल बड़ा क्रोध आता है । तो सरकार इसकी उचित व्यवस्था करे कि जो मेहनत करके कुएं से खेती करते हैं उनको कम से कम कीमत तो जरूर मिले । हमारी सरकार का यह फर्ज है कि वह शुगर फेक्ट्रियों के मालिकों को मजबूर करे कि उनको पूरा पैसा दें ताकि किसानों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले ।

सके साथ ही साथ मुझे कहना है कि हमारे वाजपेयी जी ने जो सजेशन दिया है और प्रान्तीय सरकारों ने भी इसके लिये मांग की थी कि गन्ने की कीमत दो रुपया मन होनी चाहिये उसको भी करने की आवश्यकता है, नहीं तो यदि किसानों को उचित कीमत नहीं मिलती है और मिल मालिक मनमानी ढंग से काम करते हैं तो फिर गन्ने की खेती कम होगी । हम प्लानिंग करते हैं कि इतनी खपत है और इतना बफर स्टाक में रखना है लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है और ज्यादा लोग चाय पीने लगे हैं, मिठाई खाने लगे हैं और ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो पुराने हिसाब किताब से काम चलने वाला नहीं है । तो इसके लिये कि रिकवरी अच्छी हो किसानों को हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिये, उनको इरिगेशन के लिये, खाद के लिये, मैन्योर के लिये सब सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये । केन सेस तो लेते हैं लेकिन मालूम नहीं उसका किस तरह से वितरण होता है । सड़कें अच्छी नहीं हैं, कच्ची सड़क है और बैलगाड़ी उसमें चलती नहीं है । तो जब तक हम जो गन्ने की खेती करने वाले हैं उनकी हालत पर ध्यान नहीं देंगे तब तक न गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा और न चीनी का उत्पादन होगा ।

अब, राशनिंग का सवाल आया, कंट्रोल का सवाल आया लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि जहां मिक्स्ड एकानामी है, पूंजीवादी व्यवस्था है वहां कंट्रोल कैसे चलने वाला है । जब पूरी समाजवादी व्यवस्था हो तब तो कंट्रोल को समझा जा सकता है नहीं तो हम देखते हैं कि जब कंट्रोल होता है तब भ्रष्टाचार भी शुरू हो जाता है । हमारी सुशीला नायर ने एक बार भाषण दिया कि जितने फूड के इंस्पेक्टर हैं वे कारें रखते हैं, लड़कों को विलायत भेजते हैं तो फिर आप समझ जाइये कि कंट्रोल में फायदा किसको होता है, ये जो छोटे छोटे आफिशियल्स हैं ये सब भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं । हमारे

[श्री शील भद्र याजी]

समाज में जो व्यवस्था है उसमें हम उनको कम तनख्वाह देते हैं यह ठीक है लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में, मिक्स्ड एकानामी में कंट्रोल नहीं चलने वाला है। जब तक प्योर एंड सिम्पल समाजवाद नहीं होता है तब तक कंट्रोल से सब को दिक्कत होती है। कंट्रोल को कुछ लोगों ने दबी जबान से सपोर्ट किया है लेकिन जो मौजूदा निजाम है उसमें मैं कंट्रोल का हामी नहीं हूं, इससे और दिक्कत बढ़ेगी ।

चीनी की बहुत कुछ कमी है लेकिन फिर भी चीनी है और रुपया खर्च करने पर मिलती है। हम लोगों को जरूरत पड़ती है तो मजबूरन चीनी लेनी पड़ती है और वह रुपया खर्च करने पर मिलती है। तो चीनी बाजार में है भी और मिलती भी नहीं है। इसलिये जब तक इसके वितरण करने की जो मशीनरी है उसमें सुधार नहीं होता है और जब तक आप किसानों को ज्यादा से जयादा इंसेंटिव नहीं देते हैं, जब तक उसको गन्ने की कीमत वक्त पर नहीं मिलती है और उचित कीमत नहीं मिलती है तब तक यह चीनी का संकट रहेगा। हमारे वाजपेयी जी ने कहा कि चीनी संकट बाहर भी है और भीतर भी है लेकिन मेरा कहना है कि जो भीतर का चीनी संकट है उसको हम दूर कर सकते हैं यदि हम किसानों को प्रोत्साहन दें और उसके पैदा किये गन्ने में ज्यादा रिकवरी हो इसके लिये कोशिश करें। जैसे कि यू० पी० और बिहार में इरिगेशन की व्यवस्था होनी चाहिये और मैन्योर वगैरह की भी व्यवस्था होनी चाहिये। तो अगर हम इस तरह से किसानों को मदद देते हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं फिर कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कंट्रोल-वंट्रोल को दिमाग में लाने की कोशिश न करें, शुगर-केन की प्राइस को बढ़ायें क्योंकि अगर उनको गन्ने से आमदनी होती है—यह तो कैश क्राप है—तो वह जरूर गन्ना पैदा करेंगे और इसके साथ ही इरिगेशन के लिये और मैन्योर के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री **चन्द्र शेखर** (उत्तर प्रदेश) : महोदया, इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें शुगर मिलों के इतिहास के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा और पिछले वर्षों में हमारी सरकार ने जो नीति अपनाई है उस पर भी दृष्टिपात करना होगा ।

हमारे कई मित्रों ने यह प्रश्न उठाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जो मिलें हैं वे आर्थिक ढंग से नहीं चल रही हैं। यह प्रश्न केवल उन्हीं मित्रों के सामने नहीं है बल्कि सारे देश के सामने यह प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जो मिलें हैं वे आर्थिक ढंग से चल रही हैं या नहीं ।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) in the Chair]

सन् १९३० के आसपास जब पहले पहल शुगर उद्योग हमारे देश में प्रारम्भ हुआ था तब उत्तर प्रदेश और बिहार में ही मिलें लगी थीं। उस समय जिन लोगों ने उन मिलों को लगाया था उस समय उसका आर्थिक ढांचा अच्छा रहा होगा और तबसे लेकर आज तक, दस वर्ष पहले तक, ये मिलें बड़ी अच्छी तरह से काम करती रहीं और उसके बाद फिर दक्षिण भारत में भी मिलें लगीं—मैसूर में लगीं, महाराष्ट्र में लगीं, दूसरी जगहों पर लगीं ।

एक दूसरा भी भ्रम है इस देश में जिसको मिटाना आवश्यक है। लोग ऐसा समझते हैं कि दक्षिण भारत के गन्ने में रिकवरी ज्यादा होती है और उत्तर भारत के गन्ने में रिकवरी कम होती है लेकिन अगर स्टेटिस्टिक्स को देखा जाये, अगर अंकों का समन्वय किया जाय, तो यह देखने को मिलेगा कि एक महाराष्ट्र स्टेट को छोड़ कर सारे हिन्दुस्तान में जो रिकवरी है वह करीब करीब बराबर है। मैं आपके सामने फिगर्स रखना चाहूंगा कि कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहां १९५२–५३ में ९·२७ थी, १९५३–५४ में

१०·३१ थी, १९५४–५५ में ९·५६ थी, १९५५–५६ में ९·६२ थी, १९५६–५७ में ९·९४ थी और १९५७–५८ में ९·९४ थी । यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की हालत थी । पूर्वी जिलों में भी १९५२–५३ में ९·७ थी और १९५८–५९ में ९·७८ थी । आन्ध्र में, मद्रास में, मैसूर में, केरल में यह रिकवरी के फिगर्स हैं ; १९५२–५३ में ९·९३ थी और १९५८–५९ में ९·५३ थी । महाराष्ट्र स्टेट में जो कि तब बम्बई स्टेट था वहां की रिकवरी फिगर्स जरूर ज्यादा थी—१९५२–५३ में ११·५१ और १९५८–५९ में ११·४६ । सारे हिन्दुस्तान की रिकवरी फिगर्स इस प्रकार रही हैं : जो रिकवरी १९५२–५३ में ९·९७ थी वह १९५८–५९ में ९·८५ हो गई । अगर सारे देशकी रिकवरी को लिया जाये तो एक महाराष्ट्र स्टेट अपवाद स्वरूप है, उसके अलावा कोई दूसरा प्रदेश यह नहीं कह सकता कि कि वहां के गन्ने में रिकवरी कोई बहुत ज्यादा होती है ।

श्री एन० श्री राम रेड्डी : रिकवरी की बात नहीं है । सवाल प्रोडक्शन बढ़ने का है ।

श्री चन्द्र शेखर : उसके सिलसिले में भी मैं जिक्र करूंगा । मैं यह कहना चाहता था कि ये सवाल गलत तरीके से उठाये जाते हैं । अभी कुछ मित्रों ने यह सवाल उठाया उत्तर भारत में चीनी मिलें रहनी चाहिये दक्षिण में नहीं बननी चाहियें और कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिण भारत में बननी चाहियें क्योंकि उत्तर प्रदेश की मिलें अनार्थिक हैं और उनको समाप्त हो जाना चाहिये । यह विवाद किस वजह से उठता है ? इस वजह से उठता है कि सरकार की शक्कर नीति दोषपूर्ण रही है, सरकार की शक्कर नीति किसी सिद्धान्त के ऊपर आधारित नहीं है । सरकार की नीति, जिस समय जैसा दबाव पड़ा उस समय वैसा बदल गई । किसी भी देश में शक्कर का उत्पादन या किसी अन्य वस्तु का उत्पादन बढ़ाने या घटाने में केवल एक ही दृष्टिकोण उसमें होता है, एक ही मानदंड होता है कि उस देश की खपत के लिये कितनी शक्कर चाहिये और बाहर के देशों को भेजने के लिये उस देश के पास कितना बाजार है । अगर भारतवर्ष को देखा जाये तो मैं समझता हूं—स्मरण के आधार पर मैं कह रहा हूं और कृषि मंत्री जी अगर मैं गलत हूं तो सही कर देंगे अगर चीन के एक देश को छोड़ दिया जाय तो शायद हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा, शुगर की जो खपत है वह दुनिया के देशों से बहुत पीछे है । १९६१–६२ में चीनी का उत्पादन ज्यादा बढ़ गया तो क्या कहा कृषि मंत्री ने—उत्पादन कम कर दो । १९६१ में श्रीमन् इसी सदन में एक बिल आया —शुगर रेगुलेशन आफ प्रोडक्शन बिल । मिल मालिकों को कहा गया कि दस फी सदी चीनी कम पैदा करो नहीं तो तुम्हारे ऊपर पीनल ड्यूटी लगेगी । जब इस हुकूमत ने यह कहा था तो मैं बहुत अदब के साथ इस हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश की खपत के लिये जितनी चीनी की जरूरत थी वह पूरी हो गई थी ? अगर नहीं पूरी हो गई थी तो इस आदेश का क्या कारण था ? उस समय—खाद्य मंत्री महोदय इस समय नहीं है, उनका वह भाषण मैं अभी पढ़ रहा था—उन्होंने कहा था कि अगर हम इस तरह से शक्कर के उत्पादन को अनियंत्रित ढंग से छोड़ दें तो अगले कुछ दिनों में करीब दस मिलियन टन, यानी १०० लाख टन, एक करोड़ टन, शक्कर पैदा होने लगेगी और हमारे लिये एक समस्या उत्पन्न हो जायगी । यह एक समाजवादी समाज बनाने वाली सरकार है, एक नियोजित अर्थ व्यवस्था में विश्वास रखने वाली सरकार है, जहां एक दिन में ऐसा लगता है कि शक्कर बढ़ रही है, दूसरे दिन ऐसा मालूम होता है कि शक्कर खत्म हो रही है ।

[श्री चन्द्र शेखर]

तो मैं आपसे कह रहा था कि उत्पादन के दो तीन तरीके होते हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिये । एक तो यह देखना पड़ेगा कि आज जो शक्कर की मिलें हैं उनकी डेली क्रशिंग कैपेसिटी क्या है, गन्ना खपत की उनकी ताकत क्या है । दूसरे यह कि मौसम यानी सीजन कितनी देर तक चलता है और तीसरे यह देखना पड़ेगा कि परसेंटेज आफ रिकवरी क्या है । आप इस नजरिये से सोचिये । उत्तर प्रदेश में जितनी मिलें हैं अधिकतर १९३३–१९३४ में लगी हैं । उस जमाने से आज तक पूंजीपतियों ने उस मशीनरी को माडर्नाइज नहीं किया, नए जो टेकनिक निकले उन को अपनाया नहीं । मुनाफा कमाते रहे, आज भी मुनाफा कमाते जा रहे हैं । लेकिन उन मशीनों को नये तरीके से (*Interruption*) माफ कीजिये, अपने मित्र जयपुरिया जी से मैं कहूंगा, यह सही बात है कि इन मिलों की कैपेसिटी नहीं है । ऐसा माना गया है कि किसी भी शुगर फैक्टरी की १५ सौ टन प्रति दिन की कैपेसिटी होनी चाहिये गन्ने की खपत की । उत्तर प्रदेश की बहुत सी मिलें १२०० टन से नीचे की खपत करती हैं । क्यों ऐसा होता है, हम इसको क्यों बर्दाश्त करते हैं ? आज शोर मचता है कि ये अन-इकनामिक इन्डस्ट्रीज हैं, नहीं चलेंगी । पूंजीपतियों ने कहा, जैसा कि दूसरे मित्र आज मांग कर रहे हैं, कि इन मिलों को उठा-कर दक्षिण भारत ले जाइये । कृषि मंत्री जी फिर मुझे ठीक करेंगे, अगर मैं गलती कर रहा हूं, कि पिछले सालों में अथाराइज्ड कन्ट्रोल के अन्दर दो मिलें उत्तर प्रदेश की चलीं । यही नहीं कि उनकी बिगड़ी हुई हालत ठीक हो गई उनमें मुनाफा भी होने लगा । तो मैं बड़े अदब से कृषि मंत्री महोदय से कहूंगा कि अगर शुगर मिल के मालिक उत्तर प्रदेश में मिल नहीं चलाना चाहते हैं, अगर उनको इसमें घाटा होता है, तो उन बेचारों को कष्ट आप क्यों देते हैं? क्यों नहीं सरकार उनको अपने कब्जे में ले लेती है, क्यों नहीं सरकार उनको कोआपरेटिव फैक्टरियों के अन्दर कन्वर्ट कर देती है ? सरकार करना नहीं चाहती है ।

मैं आपसे कहूं कि प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार के बारे में अभी हमारे मित्र रेड्डी साहब ने कहा है । वह सही बात है । उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और खाद वगैरह ठीक से नहीं दी जाती । उनकी बात सही है । अभी मैं जून का इन्डियन शुगर मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें किसी एक साहब का लेख निकला है—नाम मुझे उनका इस वक्त याद नहीं आ रहा है—जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो यह शुगरकेन और शुगर इन्डस्ट्री की दुर्गति है उसका एक मात्र कारण वहां की सरकारें हैं । मैं सोचता था, कोई साहब नाराज होंगे । लेकिन अभी मैं यह इंडियन शुगरकेन कमेटी की १९६१–६२ की रिपोर्ट देख रहा था । श्रीमन्, आश्चर्य होगा रेड्डी साहब को कि जितनी गन्ना विकास की योजनायें उत्तर प्रदेश में लागू हुई सबकी सब पूरी हो गई । ये स्टेटिस्टिक्स हैं—महाराष्ट्र में नहीं पूरी हुई, मैसूर में लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश और बिहार में जितना लक्ष्य रखा गया उस लक्ष्य से अधिक काम उन सरकारों ने कर दिया । तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जो हुकूमतें हैं वे स्टेटिस्टिक्स बनाने में एक खास काबिलियत रखती हैं और उस काबिलियत के बल पर हमारे कृषि मंत्री जी उनको छूट दिये हुए हैं, उनका अभ्यर्थना करते हैं ।

तो यह एक बड़ा सवाल हमारे सामने है और आप यह याद रखिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी तो आज इस दुर्दशा की अवस्था में भी करीब करीब, मैं समझता हूं ६५ फीसदी जो चीनी का उत्पादन केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में होता है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते । दूसरी बात मैं आपसे यह

अर्ज करूंगा कि गन्ना उत्पादकों के साथ यह सरकार क्या तरीका अख्तियार करती है ? १९५२–५३ में माननीय स्वर्गीय रफी अहमद किदवई साहब खराक मंत्री थे, उन्होंने कहा कि किसानों को चीनी उत्पादन के लाभ में से कुछ हिस्सा मिलना चाहिये। हर मिल मालिक ने उनकी बात को माना। सरकार ने उसे माना, पूंजीपतियों ने उसको माना, किसानों ने माना। माननीय रफी साहब ने सब लोगों को सामने बिठलाया और कहा तुमको लाभ में से इतना देना होगा और पूंजीपतियों ने उनकी बात को मान लिया। श्रीमन्, मैं आपके जरिये कहना चाहूंगा कि केवल एक साल में, १९५३–५४ में, यू० पी० की मिलों ने ५० लाख रू० गन्ना उत्पादकों को दिये। बिहार जहां से कृषि मंत्री जी आते हैं, वहां की मिलों ने बड़ी उदारता के साथ १४,००० रु० १९५३–५४ में गन्ना उत्पादकों को दिया। उसके बाद कभी भी गन्ना उत्पादकों को लाभ में से हिस्सा नहीं दिया गया। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में क्या हुआ ? वहां जितनी मिलें थीं उन्होंने १९५२–५३ में १ करोड़ रु० गन्ना उत्पादकों को दिया—यह SISMA Formula का मैं जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने श्रीमन्, १९५३–५४ में ९२ लाख रू० दिया, १९५४–५५ में ४० लाख रु० दिया, १९५५–५६ में २४ लाख रु० दिया और १९५७–५८ में भी कुछ रुपया दिया। यह कुल रुपया करीब १,०७,३७,००० रु० के दिया। ये फिगर्स मेरी नहीं हैं। खाद्य मंत्री साहब के भाषण से मैंने ये उद्धारण निकाले हैं।

4 P.M.

दक्षिण भारत के मिल मालिक मुनाफा कमायें वे दें और उत्तर भारत के न दें ? जब यह सवाल संसद् में उठाया गया कि क्यों नहीं दिया जाता तो माननीय मंत्री जी जो आज मौजूद नहीं हैं, मेरा मतलब माननीय श्री पाटिल जी से है, कहते हैं कि यह हमारी आपस की अन्डरस्टैंडिंग थी, कोई स्टैटुटरी राइट नहीं था। अच्छा साहब नहीं था। १९५८ में इसेंसियल कमोडटीज ऐक्ट के अन्दर आपने तय किया कि उनके लाभ में से हिस्सा दिलायेंगे। आपने डिफर्ड प्राइस पालिसी अख्तियार की और १९५१ से १९६२ तक का पैसा अभी तक नहीं मिला और १९६२ में आप फिर कहते हैं हम इसको लागू नहीं कर सके। यही नहीं श्रीमन्, केवल लागू नहीं कर सके बल्कि आज तक हिसाब नहीं बना सके कि उत्तर प्रदेश के मिलों के ऊपर गन्ना उत्पादकों का १९५८–६२ तक कितना बकाया है। यही नहीं कि उनको हिस्सा नहीं मिलता, उनकी पैदावार के लिए क्या यह सरकार जिम्मेदार नहीं है ? १९६१–६२ में इस हुकूमत के सामने जब कहा गया कि जितना गन्ना पैदा हुआ है उस सारे गन्ने की खपत का इंतजाम सरकार को करना चाहिये। इस पर सरकार ने कहा कि हम इस बात की कोशिश करेंगे लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि सारे गन्ने की खपत हो जाये। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अदब के साथ कहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश के एक जिले की बात जानता हूं। देवरिया जिले में किसानों ने अपने खेतों पर खड़ा गन्ना जला दिया। यह बात मैं अकेले ही नहीं कह रहा हूं। आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के सामने मुआविजा देने का मामला विचाराधीन है।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Mr. Chandra Shekhar, you will have to conclude. There are 4 more speakers before the Minister can reply.

श्री चन्द्र शेखर : वहां के किसानों ने इस तरह से अपने खेत का गन्ना जलाया क्योंकि जून और जुलाई के महीने में मिलें बन्द हो गईं और गन्ने की खपत नहीं हो सकी। यही नहीं, सन् १९५०–५१ में भी यह बात हुई १९४०–४१ में हुई थी। करीब करीब हर १० वर्ष के बाद एक क्रम आता है, गन्ने का उत्पादन अधिक हो जाता है और उसकी खपत का कोई इन्तजाम नहीं हो सकता है।

[श्री चन्द्र शेखर]

उस समय हुकूमत ने कहा केशर लगाओ, कोल्हू लगाओ और गन्ने का उत्पादन करो, उत्पादन करके गुड़ और खन्डसारी पैदा करो । जब किसानों ने अपने यहां कोल्हू और केशर लगा लिये तो सरकार १९६३–६४ में यह नहीं चाहती है और कहती है कि गुड़ तथा खन्डसारी का उत्पादन नियंत्रित होगा । श्रीमन्, मैं सरकार से यह पूछता हूं कि यह बात किसानों के ऊपर क्यों नहीं छोड़ दी जाती कि वे गन्ने की कीमत के बारे में मिल मालिकों से बातचीत करें । इसमें "केन को-आपरेटिव यूनीयन" बरकत के रूप में मिली है और बिहार तथा यू० पी० में यह काम कर रही है । जब कोई झगड़ा चलता है तो मिल मालिक की ओर से और सरकार की ओर से दलाली करने का काम इस यूनीयन का हो जाता है । मैं श्रीमन्, से कहता हूं कि आप इस सिलसिले में गौर करें, इस पर विचार करें और सोचें ।

दूसरी बात कहकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जितने ये सारे सवाल हैं उन सवालों पर गौर करते समय यह बात सामने रखें कि आज की स्थिति का क्या समाधान है, चाहे उत्तर की मिलें हों या चाहे दक्षिण की मिलें हों, मेरी अर्ज यह है कि सरकार इन्हें सहकारी समितियों द्वारा खुद अपने कंट्रोल के अन्दर चलाये । अगर यह लाजवाब समाजवादी सरकार इस काम को नहीं कर सकती तो उसको कम से कम प्राफिट के ऊपर एक सीलिंग लगा देनी चाहिये, लाभ के ऊपर एक रोक लगा देनी चाहिये और सब फैक्टरियों को बराबर का लाभ मिलना चाहिये । अगर सरकार नियोजित अर्थ व्यवस्था की बात चलाती है तो सरकार का दिमाग साफ होना चाहिये । अगले साल कितनी शूगर एक्सपोर्ट करनी है उतनी शूगर के ऊपर जो अधिक पैसा लगे और जितनी शूगर देश के अन्दर खपत होने वाली है, उनके व्यय का समन्वय कर दिया जाना चाहिए ।

सरकार से दूसरी अर्ज मैं यह करूंगा कि वह जो १३ रुपया मन एक्साइज ड्यूटी लेती है, वह सरकारी दुर्नीति का दूसरा प्रमाण है । अगर सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी को १३ रुपये से ५ रुपया कर दे तो शक्कर का ज्यादा उत्पादन होगा और इससे टोटल एक्साइज ड्यूटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा । लेकिन सरकार उसी जहनियत से काम करती है जिस जहनियत से इस देश के पूंजीपति और सरमायदार करते हैं । जितना चाहे मिल्किंग काऊ से दूध निकाल लो, अगर आज नहीं निकालोगे तो कल वह बात होने वाली नहीं है ।

तो अंत में, श्रीमान्, यह कहना चाहूंगा कि सरकार को एक सही नियोजित नीति अपनानी चाहिये और किसानों को दो रुपये मन गन्ने की कीमत देकर प्रेरणा देनी चाहिये । दूसरी बात जो मुझे कहनी है उसके लिए श्री जयपुरिया और श्री वाजपेयी जी माफ करेंगे । अगर कंट्रोल में खराबी है, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, तो इन बुराइयों को मिटाना ही पड़ेगा । अगर हम इस चीज को नहीं मिटा सकते हैं तो यह देश चन्द लोगों की मर्जी पर चलने वाला नहीं है । आप सारे देश की अर्थ व्यवस्था को कुछ लोगों के हाथ में छोड़ दें, मैं यह बात नहीं मानता हूं । मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सारे शुगर का ट्रेड स्टेट ट्रेनिंग के आधार पर होना चाहिये । उसके उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण हो, उसके लाभ पर हो, उसके वितरण पर हो, तब सही समाजवादी व्यवस्था की ओर सही उत्पादन और वितरण की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं ।

4 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Mr. Arora, I am sorry you get only five minutes.

SHRI ARJUN ARORA: I will take only five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) ; If you can do with much less, it will be better.

SHRI ARJUN ARORA: Mr. Vice-Chairman, Sir, the sugar policy of our Government seems to be determined not by the interest of the growers but the prime consideration seems to be the interest of the very vocal sugar industry in this country. The sugar industry in this country is very highly organised, I mean the mill-owners. We have an Indian Sugar Mills Association, we have the Regional Sugar Mills Associations, we have Sub-regional Sugar Mills Associations and "we find that all of them have the resource to meet in the Ashoka Hotel and cry that they are unable to make as much profit as they are entitled to and that unfortunately appears to have a great deal of influence over the Government. When there is more sugar production in the country, the industry cries that it does not have the resources to carry the stock and the Government generously comes forward, asks the banks to accept sugar and advance money and even the Reserve Bank is asked to become liberal to the banks which advance money against sugar. When there is less sugar and controls are to be imposed, it is not the sugar industry which suffers. The sugar industry remains untouched. Its profits are guaranteed. The Tariff Board formula is there to guarantee the profits. Even their wholesalers, their agents, who are appointed by the sugar industry, are not touched, it is tine poor retailer, the poor broker, the poor darogh and the poor phtttkar *dukan-dar* who is affected by controls and that is what has happened since 17th April. The Government offers incentives to the industry and though all these learned speakers who have preceded me have mentioned sugarcane as the prime commodity in this sugar industry, somehow the sugar industry is always able to persuade the Government that it is the industry, the factory-owners who need incentives and not the jgrower. As a matter of fact when the grower does his duty by the country and produces more sugarcane, he is made to suffer. There have recently been two years during which sugar production rose. The years were 1959-60 and 1960-61.

In 1959-60 sugar production was 24 lakh tons. In 1960-61 sugar production was 30 lakh tons. This increased production was not because of something which the industry did. It was possible because of the fact that the cane growers in the country produced more sugarcane. Many owners of sugar factories suffer from diabates, but that does not produce sugar which anybody can consume. So this 30 lakh tons of sugar was produced because the cane growers did their duty by the country. And how did the Government react to it? The Government was once more influence-ed by the industry. And you know the industry makes more profit when there is scarcity. The industry makes more profit even when there is an artificial scarcity. The industry said, "All these stocks of sugar are there and so we will not be able to buy sugarcane next year. We will not be able to run our industry next year," So the Government imposed 'restriction on the acreage under sugarcane. The Government carried on propaganda and the Government wanted the acreage to be reduced by 10 per cent. The result was that more than 10 per cent was reduced.

{Time bell rings.) Another instance of the disincentives which are being offered by the industry and under the influence of the industry, by the Government, to the sugarcane growers is this. We have now reached a stage in which the sugarcane growers do not get the price for their cane on delivery. If the sugar industry delivers a few bags of sugar to you or me, Sir, we are made to nay the price immediately. The consumer goes to a retail shop, or a fairprice shop or a government-run shop or a cooperative shop and he has to pay the price of tbe sugar he buys immediately. But the sugar

industry in this country is a very privileged class. It does not pay the sugarcane grower the price of his sugarcane on delivery, (Time bell *rings.)* Please let me finish my sentence. The sugar industry does not pay the sugarcane grower the price of the cane on delivery. The grower is asked to wait till the season is over, till the sugar yield has been worked out and till all the complex formulae which the sugarcane grower does not understand, are used for determining the price which he is to be paid. It is this privilege of getting the sugarcane without paying the price for it which the industry has extracted which has hit the sugarcane growers in the eountry. Particularly in U.P. and Bihar where alternative crops are available the grower is today disinclined to produce sugarcane. I urge lipon the Government to give up this policy and to ensure that the sugarcane grower is treated as any other grower is treated. The cotton growers or the jute growers get paid as soon as they deliver the commodity. But the sugarcane grower is asked to wait for years together. The result is that the sugar industry in U.P. and Bihar particularly—I do not know much about others, they may be equally bad—but in U.P. and Bihar, the sugar industry is the worst pay-master. The industry owes crores to the growers. As a matter of fact, there are people who say that the sugar industry in U.P. and Bihar owes more to the growers than even the original capital invested in the whole industry. So there is some force in . . .

(Time bell rings.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): That will do, Mr. Arora. There are three more speakers.

SHRI ARJUN ARORA: I am just finishing. So there is some force in what Mr. Chandra Shekhar sa'd that the sugar industry in U.P. and Bihar where the industry says it is not working profitably today, should be taken over and handed over to the growers to whom the industry already owes so much money.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Shri Murahari. Please be brief.

श्री गोडे मुराहरि (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष जी, शक्कर के दामों के ऊपर विचार करते वक्त हमें यह भी देखना है कि इन दामों को निर्धारित करने में कौन कौन से फैक्टर्स सामने आते हैं । एक तो मिल मालिकों का नफा और दूसरा सरकार का टैक्स । मेरा कहना यह है कि जो दाम बढ़ता है, उसका एक दोषी मिल मालिक है और दूसरा दोषी सरकार है; क्योंकि सरकार की नीति रही है और जो एक्साइज उसने उस पर लागू किया है उससे भी हमारे देश में जो शक्कर का दाम बढ़ता जा रहा था वह और बढ़ता जा रहा है । लेकिन आज की जो परिस्थिति है वह इसलिये उत्पन्न नहीं हुई कि सरकार का सेस इतना ज्यादा है । असल में जो गलत नीति हमारे कृषि मन्त्रालय ने चलाई है शक्कर के बारे में और दूसरे उत्पादनों के बारे में, उसका नतीजा यह है कि आज हम यह देख रहे हैं कि हमसे यह कहा जाता है कि शक्कर का उत्पादन उतना नहीं है जितना कि देश के लिये जरूरी है ।

अभी कुछ साल से हमने शक्कर एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है । क्यूबा ने जब अपनी शक्कर अमेरिका भेजना बन्द कर दिया उसके बाद से हिन्दुस्तान से शक्कर एक्सपोर्ट होने लगी । वह भी एक कारण हो सकता है, जिससे शक्कर के दाम में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो नीति हमारी सरकार ने अपनाई है उस से नुकसान सिर्फ गन्ना पैदा करने वाले किसान का हुआ है और किसी का नहीं हुआ है । जो किसान गन्ना पैदा करता है उसको दो रुपये मन सन् १९४७ में मिला करता था और आज मिल रहा है, एक रुपया चार आने मन । किसान का जो इस में नुकसान हुआ है करीब १५ करोड़ रुपया, उसकी तरफ कोई नहीं देखता । तब से लगातार

गन्ने का जो भाव है, उसमें कटौती होती रही है और जो मिल मालिकों का दाम है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। तो यह जो पालिसी है सरकार की, इससे हमारा जो किसान है उसको इंसेंटिव देने के बजाय और नुक्सान पहुंचाया जा रहा है यानी आज न्यायपूर्वक जो उसको मिलना चाहिये वह भी उस को नहीं मिल पा रहा है। इसलिये आज यह कहना कि शूगरकेन का प्रोडक्शन कम हो गया है, इस का सारा दोष सरकार पर आता है। एक तो किसानों को जो भाव मिलना चाहिए उसमें कटौती हुई है और दूसरे जो पालिसी सरकार ने चलाई है कि शूगरकेन का प्रोडक्शन कम होना चाहिये उससे सिर्फ न वे जितना चाहते थे उतनी कमी हुई है, बल्कि इस संबंध में जो एक जनरल पालिसी चलाई गई है और एक प्रोपेगन्डा किया गया है कि शुगरकेन प्रोडक्शन कम किया जाय उस से आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि किसान यह समझता है कि शुगरकेन के प्रोडक्शन में कोई लाभ नहीं है और जो प्रोडक्शन शूगरकेन का हो भी रहा है वह और जगह जा रहा है जैसे गुड़ बनाने में या खंडसारी बनाने में क्योंकि वहां उसको ज्यादा दाम मिलता है। हमारी प्रोहिबिशन की जो पालिसी चली है उससे भी उन की गुड़ और खंडसारी का दाम बढ़ गया है, क्योंकि उसमें उनको ज्यादा नफ़ा होता है। तो यह सारी जितनी पालिसी सरकार की तरफ से चलाई गई है, उसका नतीजा यह हुआ है कि आज शक्कर की शार्टेज हिन्दुस्तान में पैदा हो गई है और साथ ही साथ इस शार्टेज का नियंत्रण करने के लिये जो हमारी सरकार की पालिसी है उस में एक तो कंट्रोल बताते हैं कि हम कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल करके यह जो शक्कर है इसका डिस्ट्रीब्युशन करेंगे। मैं तो कंट्रोल के पक्ष में हूं और मैं इस से सहमत नहीं हूं कि कंट्रोल बिल्कुल हटा दिया जाय; क्योंकि जब तक आप के पास शूगर का इतना स्टाक नहीं हो कि कम्पीटिटिव प्राइस में बाजार में बेच सकें तब तक कंट्रोल की जरूरत है। लेकिन कंट्रोल को जब लागू करते हैं तब सरकार को भी सख्ती से उसको लागू करना है और जो बेचने वाले हैं उन के ऊपर भी सख्ती से लागू करना है। मगर कंट्रोल हम लागू करते हैं और ब्लैक मार्केट में शक्कर बेची जाती है, ब्लैक मार्केट में ज्यादा दाम पर लोगों को शक्कर मिल रही है, जिस दूकान पर कंट्रोल प्राइस पर शक्कर बेचने की बात है वहां शक्कर नहीं है—तो यह पालिसी क्या है? यह हमको क्या रिलीफ देगा और इससे क्या फायदा होगा उस में हमें बड़ा डाउट होता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कंट्रोल करते वक्त उसमें वह सख्त ऐक्शन ले। जो शक्कर ज्यादा दाम पर बेचता हो और जो दूकानदार यह कहे कि हमारे पास शक्कर नहीं है, यानी जो कंट्रोल प्राइस पर शूगर बेचने की दूकानें हैं उनमें यह कहा जाय कि शूगर हमारे पास नहीं है, इन दोनों पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। अगर सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी तब तो कंट्रोल सफल होगा नहीं तो यह कंट्रोल एकदम विफल होगा।

(Time bell rings.)

इसलिए मैं कहता हूं कि किसानों को जो भाव मिलना चाहिये वह मिले और साथ ही साथ जो परिस्थिति है, उसको कंट्रोल के जरिये दूर करना है और कंट्रोल ऐसा लागू किया जाय कि जो कानून के खिलाफ काम करे उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Shri Ghani, can you do with five minutes?

شری عبدالغنی (پنجاب) :

میں نے سب تقریروں کو غور سے سنا - مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس اندھی سرکار کو بہرہ پرائم منسٹر

[شری عبدالغنی]

شری جواہر لال کھیلتے چلا جا رہا ہے - اندھے کو دکھائی نہیں دیتا، بہرے کو سنائی نہیں پڑتا - سارے سنسار میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی بھوکا مرتا تھا تو ہمارے بھارت کی طرف چلا آتا تھا - یہاں سب کو ان ملتا تھا، کھانے پینے کو ملتا تھا، جنتا سکھی تھی، رام راجیہ تھا، لیکن اب جو اپنا رام راجیہ آیا، جواہر لال کا راج آیا، تو ...

श्री विमल कुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश) : अब रामराज नहीं चल रहा कामराज चल रहा है ।

شری عبدالغنی: وائس چیرمین صاحب - میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ کسان دکھی ہے - پنڈت جی تو کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے اور وہ جھگڑا کرتے ہیں لوہیا جی سے کہ تین آنے فی کس آمدنی ہے یا زیادہ آمدنی ہے یا زیادہ آمدنی ہے - حقیقت یہ ہے کہ ان کسانوں کی تین آنے فی کس آمدنی بھی نہیں ہے - اگر پرکھیتا کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کی حالت انتہائی نازک ہے، انتہائی خراب ہے - دوسری طرف سرکار کہتی ہے اگر پروڈکشن زیادہ ہو گیا، اگر چینی زیادہ پیدا ہو گئی، تو اس سے ایک نئی سمسیا پیدا ہو جاتی ہے - او وہ سیس لگاتے ہیں اور جو کاشت کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اتنی زمین پر نہ کرو کیوں کہ اس سے ہمارا کام نہیں چلے گا اور ہم کو مشکل پڑے گی - تیسری طرف مل والے شور مچاتے ہیں کہ چینی پڑی ہے ہم گنا خریدیں کیسے -

تو وائس چیرمین صاحب - آپ ہی فیصلہ کریں کہ سچا کون ہے - آیا کسان جو دکھی ہے وہ سچا ہے یا مل والے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چینی زیادہ ہو جاتی ہے کیسے مل کر چلائیں، وہ سچے ہیں یا ہماری سرکار سچی ہے کہ کبھی کہتی ہے کہ بہت ہونے لگی ہے اور کبھی کہتی ہے کہ بہت کمی ہو گئی ہے - خیر کوئی نہ کوئی سچا ہے - میری اپنی رائے یہ ہے کہ سرکار کو اپنے آنکڑوں کی بھول بھلیاں سے جنتا کو پاگل نہیں بنانا چاہیئے - دنیا پاگل نہیں بننے والی ہے - کیوں - جب ہم کہتے ہیں تو پنڈت جی سنتے نہیں ہیں اور جب اپنے من میں آتی ہے تو وہ پاٹل صاحب کو جن کی پالیسی پر اس وقت نکتہ چینی ہو رہی ہے، ... ن دوشی ٹھہرائیں یا دوشی ٹھہرائیں، ان کو نکال کر پھینک دیتے ہیں - وائس چیرمین صاحب - یہ عجیب دیش ہے - ایسا دیش میں نے کوئی دیکھا نہیں کہ جس میں ایمرجنسی کے زمانہ میں جب کہ خطرہ انتہائی ہو اس وقت اپنی ...

جن کو وہ لائق سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ غلط ہیں، لیکن وہ لائق سمجھتے ہیں، اور لائق ترین منسٹروں کو نکالتے ہیں - اس لئے نہیں نکالتے کہ ایمرجنسی ہے اور ایمرجنسی کا مقابلہ کرنے کے لئے تم دیش کی حفاظت میں ڈٹ جاؤ بلکہ کہتے ہیں کہ پارٹی کی نیا ڈوب رہی ہے یا منسٹری ڈوب رہی ہے اس لئے اس پارٹی کو مضبوط کرو -

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Ghani Sahab what has that to do with this?

<u>شری عبدالغنی</u> : وائس چیر مین صاحب - وہ اس لئے کہ سارا دوش سرکار کا ہے - میں اس لئے کہتا ہوں کہ یہ شارٹیج نہیں ہے، یہ بناوٹی چیز ہے -

وائس چیرمین صاحب - کبھی دنیا میں ایسا نکما کوئی لیڈرشپ میں نے دیکھی نہیں کہ ایمرجنسی کے دور میں وہ ساری پارلیمنٹ کو دھکا دے دے، دونوں هاوسوں کا اپمان کرے - کسان کے نام پر یا یہ جو سرمایہ دار ہے جو لوٹ رہا ہے، جو کھسوٹ رہا ہے، اس کے نام پر، ایسی اندھیر گردی مچائی کہ اس وقت شارٹیج کی بات کہتے ہیں - یاجی جی بڑے غصہ میں آئے اور کہا کہ چائے میں دو دو چمچ چینی ملاتے ہیں – آپ بھی جانتے ہیں وائس چیرمین صاحب - کہ مجھے پندرہ برس کے بعد پہلی بار راشٹرپتی سے ملنے کا موقعہ ملا تو وہاں چائے بھی چلتی ہے، ہزاروں مہمانوں کے لئے اور ساتھ میں شربت بھی چلتا ہے اور مٹھائی بھی چلتی ہے – وہاں سب کچھ مل جاتا ہے لیکن غریب کسان کی لڑکی کی شادی ہو تو اس کو چینی نہیں ملتی ہے - تو یہ جو اس کو نہیں ملتی ہے اس کا ایک راستہ نکالنا چاہیئے اور وہ ہے کہ سرکار سے کہو کہ دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا- سراسر موم ہو یا سنگ ہو جاؤ - یا تو کنٹرول کرے یا کنٹرول نہ کرے لیکن یہ اسی طرح سے نہ ہو جیسے کہ شراب پر کنٹرول ہے -

(*Time bell rings.*)

میں آپ کا حکم مانوں گا - مجھے آپ کا پورا ادب ہے - میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سرکار کی اپنی حرکت ہے، اس کی اپنی زیادتی ہے، ایسی نکمی سرکار کو نکالنا چاہئے - صبح ہمارے کمیونسٹ بھائی ہمیں طعنہ دینے لگے کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے کہنے پر پاٹل کو اور مرارجی کو نکالا تو تم بھی تو یہ کہتے تھے – میں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے تھے، ہم نے کہا کہ ان کی ماں جواہر لال کو نکالو جب تک ان کو نہیں نکالو گے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا - ان کو نکالنے کے بعد ہم چین لیں گے -

†[**श्री अब्दुल गनी** (पंजाब) : मैंने सब तकरीरों को गौर से सुना । मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस अन्धी सरकार को बहरा प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहर लाल खींचे चला जा रहा है । अन्धे को दिखाई नहीं देता । बहरे को सुनाई नहीं देता । सारे संसार में यह बात मशहूर थी कि जब कोई भूखा मरता था तो प्यारे भारत की तरफ चला आता था । यहां सब को अन्न मिलता था, खाने पीने को मिलता था, जनता सुखी थी, राम राज्य था, लेकिन अब जो अपना राम राज्य आया, जवाहर लाल का राज आया, तो

श्री बिमल कुमार मन्ना लाल जी चौरड़िया (मध्य प्रदेश) : अब रामराज नहीं चल रहा, कामराज चल रहा है ।

श्री अब्दुल गनी : वाइस चेयरमैन साहब, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि किसान दुखी हैं, पंडितजी तो कहते हैं कि सब अच्छा है और वह झगड़ा करते हैं लोहिया जी से कि तीन आने फी कस आमदनी है या ज्यादा आमदनी है, हकीकत यह है कि इन किसानों की तीन आने फी कस आमदनी भी नहीं है । अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाये तो उन की हालत इंतहाई नाजुक है, इंतहाई खराब है । दूसरी तरफ सरकार कहती है अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, अगर चीनी ज्यादा पैदा हो गई, तो उस से एक नई समस्या पैदा हो जाती है । तो वह सेस लगाते हैं और जो काश्त करते हैं उन से कहते हैं कि इतनी जमीन पर न करो क्योंकि इस से हमारा काम नहीं चलेगा और हम को मुश्किल पड़ेगी । तीसरी तरफ मिल वाले शोर-मचाते हैं कि चीनी पड़ी है, हम गन्ना खरीदें कैसे ?

तो वाइस चेयरमैन साहब, आप ही फैसला करें कि सच्चा कौन है । आया किसान जो दुखी है वह सच्चा है या मिल वाले जो कहते हैं कि हमारे पास चीनी ज्यादा हो जाती है कैसे मिल को चलायें वह सच्चे हैं या हमारी सरकार सच्ची है कि कभी कहती है कि बहुत होने लगी है और कभी कहती है कि बहुत कमी हो गई है । खैर कोई न कोई सच्चा है । मेरी अपनी राय यह है कि सरकार को अपने आंकड़ों की भूल-भुलैयां से जनता को पागल नहीं बनाना चाहिये । दुनिया पागल नहीं बनने वाली है । क्यों, जब हम कहते हैं तो पंडितजी सुनते नहीं हैं और जब अपने मन में आती है तो वह पाटिल साहब को जिन की पालिसी पर इस वक्त नुक्ताचीनी हो रही है उन्हें निर्दोषी ठहरायें या दोषी ठहरायें उन को निकाल कर फैंक देते हैं वाइस चेयरमैन साहब, यह अजीब देश है । ऐसा देश मैंने कोई देखा नहीं जिस में एमरजेन्सी के जमाने में जबकि खतरा इंतहाई हो उस वक्त अपनी केबिनेट के लायक तरीन मिनिस्टरों को जिन को वह लायक समझते हैं, हम तो समझते हैं गलत हैं, लेकिन वह लायक समझते हैं, और लायक तरीन मिनिस्टरों को निकालते हैं । इसलिए नहीं निकालते कि एमरजेन्सी है और एमरजेन्सी का मुकाबला करने के लिए तुम देश की हिफाजत में डट जाओ बल्कि कहते हैं कि पार्टी की नैया डूब रही है या मिनिस्टरी डूब रही है इसलिये इस पार्टी को मजबूत करो ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Ghani Sahab, what has that to do with this?

श्री अब्दुल गनी : वाइस चेयरमैन साहब, वह इसलिए कि सारा दोष सरकार का है । मैं इसलिए कहता हूं कि यह शारटेज नहीं हैं, यह बनावटी चीज है ।

वाइस चेयरमन साहब, कभी दुनिया में ऐसा निकम्मा कोई लीडरशिप मैंने देखा नहीं कि एमरजेन्सी के दौर में वह सारी पार्लियामेंट को धक्का दे दे, दोनों हाउसों का अपमान करे, किसान के नाम

†[ ] Hindi transliteration.

पर या यह जो सरमायेदार हैं, जो लूट रहा है, जो खसोट रहा है, उस के नाम पर ऐसी अंधेरगर्दी मचाई कि इस वक्त शारटेज की बात कहते हैं, याजी जी बड़े गुस्से में आये और कहा कि चाय में दो दो चम्मच चीनी मिलाते हैं । आप भी जानते हैं वाइस चेयरमैन साहब, कि मुझे १५ बरस के बाद पहली बार राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिला, तो वहां चाय भी चलती है हजारों मेहमानों के लिए और साथ में शर्बत भी चलता है और मिठाई भी चलती है । वहां सब कुछ मिल जाता है लेकिन गरीब किसान की लड़की की शादी हो तो उस को चीनी नहीं मिलती है । तो यह जो उस को नहीं मिलती है उस का एक रास्ता निकालना चाहिये और वह यह है कि सरकार से कहो कि "दोरंगी छोड़ कर यकरंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा" या तो कन्ट्रोल करे या कन्ट्रोल न करे लेकिन यह इसी तरह से न हो जैसे कि शराब पर कन्ट्रोल है ।

(*Time bell rings.*)

मैं आप का हुक्म मानूंगा । मुझे आप का पूरा अदब है । मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि यह सब सरकार की अपनी हरकत है इस की अपनी ज्यादती है, ऐसी निकम्मी सरकार को निकालना चाहिये । सुबह हमारे कम्यूनिस्ट भाई हमें ताना देने लगे कि तुम कहते हो कि हमारे कहने पर पाटिल को और मोरारजी को निकाला, तो तुम भी तो यह कहते थे मैंने कहा कि हम यह नहीं कहते थे हमने कहा कि उन की मां जवाहर लाल को निकालो, जब तक उनको नहीं निकालोगे कुछ ठीक नहीं होगा, उनको निकालने के बाद हम चैन लेंगे ।]

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICUL-TURE (SHRI A. M. THOMAS): Mr. Vice-Chairman, I am glad that Government has been given this opportunity to make its position cleir in respect of the present position which we And ourselves in with regard to sugar. Sir, Shri Vajpayee made a I speech in Hindi and I have got before me a literal translation of his speech in English and I went through that but even before that, even while he was speaking, because of his powerful eloquence, excellent diction and his gestures, gestures also form part of eloquence, I could follow his speech, Sir. In fact, the position that we find ourselves in now consequent on the measures taken by Govern-ment has in a way been appreciated by several Members. In fact, the trend of the debate indicated that they have not very serious objection to the measures that have been taken by the Government, especially on the 17th April this year. The control that was introduced on the 17th April was inescapable and I am happy, Sir, the measures taken by Government have been generally appreciated. What was the position that we found ourselves in at the beginning of the sugar season 1962-63? Could anybody have expected a shortfall of sugar to the extent that there would be an overall production of only 21-5 lakh tons in the sugar year 1962-63? Sir, I have got figures with me. When the sugar season 1962-63 started, we had a carryover of 10-26 lakh tons, more than a million tons, of stock with us. Of course, there was some shrinkage in acreage; it had come down to 54,89,000 acres. But with the prospect of a normal crop nobody could have expected that there would be such a substantial drop in production.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: Don't you believe in the usual cycles'

SHRI A. M. THOMAS: I will come to that. In 1959-60 with an acreage of 52 lakhs we had a production ot 25 lakh tons; it was 24-82 lakh tons or roughly 25 lakh tons. The acreage in 1962-63 was more by about two lakh acres over the area cultivated in 1959-60. Naturally we expected, having regard to the installed capacity of 26-4 lakh tons—when we produced 25 lakh tons in 1959-60 the installed capacity was only 21 lakh tons and when we produced 30 lakh tons in 1960-61 the ins-

[Shri A. M. Thomas.]

tailed capacity was only j 24 Iakh tons—there would toe no difficulty at all about required production. So with the expectation of a normal crop and normal production we thought we could enter into commitments to the extent of five lakh tons for export. The actual eommitments came to only 4'38 lakh tons; one lakh tons was the balance left out of our export commitments so that we had to export in the sugar year 1962-63 a little over five lakh tons, to be exact, 5:4 lakh tons. Now, how did this situation arise? This anticipation was made in the beginning of the sugar year 1962-63. But much against our expectations we found that because of failure of rains during the period of optimum growth, that is, between July to September, because of frost and incidence of pests which resulted in lesser yield per acre the sugar production came down to 21| Iakh tons. Nobody could have expected that the production would be so low as 21! Iakh tons. The hon. Shri Jaipuria was finding fault with the Government with regard to the estimate of production for this year. Let me ask Shri Jaipuria—he is also a prominent industrialist in the sugar industry^—what was his estimate of production in December 1962? When the crushing season had started, when the position of the crop was known «ven then the estimate of the sugar industry was 24 to 25 lakh tons. If as was envisaged, the production had been 24 to 25 lakh tons, we would have had no difficulty at all. We could have without difficulty fulfilled our export commitments; we could have met the increased consumption requirements within the country and there would have been no difficulty at all. And there was a carry-over *ot* more than a million tons of sugar with us.

SHRI SITARAM JAIPURIA:' They could only presume . . .

SHRI A. M. THOMAS: I do not yield because the time is short. Sir, it is very easy to be wise after the event. Barring this cycle to which Shri Govindan Nair referred these ntural calamities which were abnormal could not have been foreseen.

SHRI G. MURAHARI: Whenever there is failure you bring in natural calamities.

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Order, order. Let the Minister proceed. He has no time.

شری عبد الغنی - کورم نہیں ہے -

[श्री अब्दुल गनी : कोरम नहीं है ।]

SHRI A. B. VAJPAYEE: But he is making wrong statements.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M, GOVINDA REDDY) : You can reply.

SHRI A. M. THOMAS: With the decontrol of sugar in September 1961 the consumption of sugar also went up. In 1961-62 the consumption was 25 lakhs 87,000 tons or roughly 26 lakh tons. The consumption trend was that it would be about two lakh tons more than that in 1961-62 and if the position was not regulated or controlled, the consumption would have been to the extent of 28 lakh tons. And we had an export commitment of 5 lakh tons.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: On a point of Order, the hon. Member has raised the question of quorum. After that the House cannot proceed.

(Quorum bell rings.)

SHRI G. MURAHARI: The ruling party should be ashamed that they are not able to maintain proper quorum.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: What about the Opposition Benches? (Interrwptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) ; Order, order. There is no sense in all this discussion. Let us see whether we can get the quorum. *(After a pause)* Now there is quorum. Let the Minister proceed.

f[ ] Hindi transliteration.

SHRI A. M. THOMAS: Now several H Members found fault with the Gov ernment about regulation of produc tion in the year 1961-62. In fact, even a usually well-informed Member like Shri Sri Rama Reddy characterised the step that was taken by the Gov ernment in 1961-62 as a blunder. I am sure after this explanation of mine each and every Member would feel satisfied about the wisdom of that measure consistent with the circum stances obtaining then. What was the position when the sugar year 1961-62 started? It was only in that year | there was this regulation of produc- j tion. Regulation of production does j not mean that the sugarcane that is produced should be allowed to rot or waste. In fact the Government want, ed to keep a balance between the quantity that will be utilised for crystal sugar, the quantity that will be utilised for khandsari and the quantity that will be utilised for jaggery. In fact early November before the start of the season we wanted to give information to the agriculturist that the crystal sugar production would ' be only to this extent, that there should be a ten per cent, reduction in production. But that ten per cent, decrease when worked out according to the formula then applied would result only in about 4 per cent, reduction; that is to say we wanted to have a production of 28 to 29 iakh tons.

SHRI ARJUN ARORA: But, Sir . . .

SHRI A. M. THOMAS: I wish the hon. Members listen and try to know the position.

SHRI ARJUN ARORA: We know the position.

SHRI A. M. THOMAS: Then they would not have criticised what the Government did. Sir, the carry-over stock was l?-6 lakh tons and what was the acreage then? More than 30 lakh tons of sugar was produced on an acreage of 57 lakhs in 1960-61, and in 1961-62 the acreage came to more than 59 lakh acres. Suppose consistent with the trend of production in 1960-61 sugar was produced in 1961-62, what would have been the position? As I said there was a carryover of 12- 6 lakh tons and the acreage was the largest on record. With an internal consumption of 23 lakh tonnes—it was only 21 lakh tonnes the previous year—it was not possible to export anything more than 3 lakh tonnes. In the first place, there was a restriction, because under the International Sugar Agreement, we had a quota of only 1:5 lakh tonnes. We had the quota that had been given by the U.S. Government. So, we had to work within that quota. We could not have exported more than 3 lakh tonnes even if we were prepared to incur a loss to the extent of Rs. 500 per tonne because the sugar price came down to £ 22 per ton. Now what was the position in which the industry was finding itself? Cane price arrears in July 1961 came to Rs. 10 crores, whereas this year in July—it means months after the season was over, delivery of the cane was over—the corresponding figure is only a little more than Rs. 2 crores. So, it was five times the normal arrears of cane price. Then, there was shortage of space in the various factories In fact, the various factories had their own storage space. But taking into account the entire storage space possessed by the factories, they were about 6 lakh tonnes storage space short. There was a risk of deterioration of 4 to 5 lakh tonnes of sugar. It is a perishable commodity. Every Member knows it. There was this situation, *viz.*, heavy carry-over, largest acreage on record, heavy arrears of cane price, etc. Then, with regard to bank advances we had to intervene and the Reserve Bank raised it to Rs. IOO crores. Even then it was not possible for the industry to pay the sugarcane grower. If we had left production unregulated, the prospects in 1961-62 were that the production would be round about 33 lakh tonnes or 34 lakh tonnes. What would we have done with that production? Now, it is very easy to be wise after

[Shri A. M. Thomas.] the even. Could we have anticipated that even with the less acreage, pro duction would have gone down to 21.5 lakh tonnes in 1962-63? Could we have anticipated that there Would be shortage throughout the world, that the best crop in Europe would have failed, that the Cuban crop would have failed. Could we have anticipated that the sugar price would be £105, five times the price that we were getting for it? Could we have anticipated that the Inter national Sugar Conference would not come to any agreement with regard to quotas and that we c'ould have exported any quantity that we would have liked? So, these are events which happened after the measures that we had taken in 1961-62. I say, Sir, for any responsible Government that was the only course open at the time when the sugar season of 1961-62 started. And in this House and in the other House questions after ques tions were put by Members. "What are you going to do with the surplus? There is a crisis of surplus." Debates were raised. Questions were asked. Then, if the Government had kept quite and if the sugar had deteriorat ed, the industry would have suffered. The industry suffering means the sugar grower also suffering. I may also say that, in spite of this regula tion of production as I have already said, not a single cane was allowed to rot 'or to get dried up. What had not gone towards the manufacture of gur or jaggery would have come to Mills. Although their quotas were fixed, whenever any sugar factory reported shortage, we immediately allocated that quota to other factories which could use it. There was not a single factory in this country which had asked for additional quota and had not been given, so that if they were in a position to crush, they were allowed to crush. You must also take the sugarcane that would have i-one to gur. At that time, the gur price was also not uneconomic. It was rising. It was worth while for the sugarcane grower to go in for jagarry manufacture. As far as the sugar-cane grower was concerned, there was aDsolutely no hardship. The regula tion of production also virtually did not result in any material reduction, it resulted in a sugar production of 27.1 lakh tonnes. We thought it to . to 29 lakh tonnes. Because ot the state of the crop then, it was not possible to produce more. So, it is rather painful to find criticism even in the press, in responsible press, and also a tendency among Members of Parliament, even among the public—public memory is short—to blame the Government, saying that the present situation has been because of the policy that has been adopted by the Government in the year 1961-62. I refute that charge and I think, having regard to the circumstances narrated by me, there was no other courts open to the Government.

Now, the hon. Mover, Shri Vajpayee, suggested that it is advisable to have partial decontrol. Shri Jaipuria even went to the extent of saying that we shall have absolute decontrol. I am happy that these two Members have been answered in a way by Shri Sri Rama Reddy as well as by my hon. friend, Shri M. N. Govindan Nair. With regard to the partial decontrol suggestion, which has been made by certain sugar merchants' associations, especially from Kanpur—in fact they have met me—I have got it examined. If that is accepted and partial decontrol duced, according to me it will result in great confusion. In fact, it was once tried in 1950-51 and 1951-52. When there was statutory rationing this was tried and the results were not satisfactory. Even in the previous control period, that is, when we introduced control in July 1958, at that time the ex-factory price was fixed only for U.P. and north Bihar. There was absolutely no restriction with regard to the prices that could be charged in Maharashtra and in the South. Shri Vajpayee seems to have mentioned that it is after the Ministers from the South have come that there is some sort of discriminatory treatment towards factories in the

North. In fact, Shri Ajit Prasad Jain was the Minister then. He is from U.P.

SHRI ARJUN ARORA: No, no. He is from Mysore.

SHRI A. M. THOMAS: At that time he represented U.P. The House might recollect that in July 1958, when there was only partial c'ontrol, ex-factory prices were fixed only in U.P. and Bihar. Only 25 per cent of production the Government took under their control and distributed to its nominees. The factories could deal with the rest 75 per cent as they liked. The only thing was . . .

SHRI SITARAM JAIPURIA: Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) : Order, order.

SHRI STARAM JAIPURIA: If I am not allowed to interrupt, how will I be able to explain the position? I should be given a chance.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) : There is no time left.

SHRI A. M. THOMAS: We find from that partial control to be not a success. In July 1959 we had to take under control all the sugar produced in U.P. and Bihar and the entire thing Was distributed according to our instructions and according to the allotments that we were making. So, once this partial decontrol was tried to a certain extent and it was found to be a failure. Now, it is not possible, have-ing regard to the stock position, to try any other experiment except the course of action that is now being followed by the Government.

Now, Shri Sri Rama Reddy said .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) : Mr Thomas, you wiH have to leave some time for the Mover to reply.

SHRI A. M. THOMAS: I think the House woul$_d$ expect that the points that have been raised should be answered. Shri Sri Rama Reddy asked: having regard to the stock position, what are you going to do for November? I may tell him that he will not have to use even a spoonful less sugar in November. I have on a previous occasion, when answering a question in this hon. House, mentioned the allotment that has been made with the existing stock—that is to $_s$ay we will be releasing 2,26,000 tons on 30th August, 1,40,000 tons on 1st October, and 1,00,000 tons on 22nd of October, so that for the first week of November there will not be an$_v$ difficulty, And in our scheme of things, and even without the scheme of things there are factories which will start in October, and as the factories produce, we would be releasing that, so that I might say that for the normal supply in November and subsequent months there need not be any anxiety at all.

Shri Jaipuria and other Members also raised the question as to how we are going to produce thes$_e$ 23 lakh tons for 1963-64. We have in fact allocated quotas for the vari'ous States. You will find that in the year 1960-61, as I have already pointed out, with an installed capacity or 24 lakh tons we have produced 30,39,000 tons. Fer the year 1963-64 we have got 26-8 lakh tons. Some installed capacity wiH now come. We will hav$_e$ an installed capacity of 23 lakh tons for the sugar year 1963-64. Could we not normally expect with the steps that we are taking to reach the production target of 33 lakh tons? I think it would be possible, and no efforts are being spared in the direction of achieving this target of 33 lakh tons. What has happened in this year itself? If U.P. and Bihar are taken out, with regard to the rest, in Maharashtra, South and in all these regions the production this year has also been normal. It was more or less the figure of last year's produc-| tion. It is 4 to 5 lakh tons less than

[Shri A. M. Thomas.] last year's production in the State of Uttar Pradesh. In U.P. in the year 1960-61 they were able to produce more than 14 lakh tons. This year the target fixed for U.P. is 15 lakh tons.

SHRI SITARAM JAIPURIA: There *ls* no sugar mill working at all at present.

SHRI A. M. THOMAS: I am surprised as to whether the hon. Member has the good of the public at heart that he should even now try to raise this scare. I am going to tell him that whatever scare he might raise, no efforts would be spared in the direction of achieving this target of 33 lakhs tons.

SHRI SITARAM JAIPURIA: I pray, it would be possible.

SHRI A. M. THOMAS: I think it would be possible to do that. What is the state of the crop? The information that I have got is that this year the state of the crop is good. Reports of sugarcane sowings and conditions of the crop received so far are encouraging. Much will depend on the rainfall and climatic conditions during the optimum period of growth of the crop, July to September. This year the monsoon was a little delayed. This month we had good rain and I hope next month also the rains will be good. If the rains are good and with the other steps we are going to take in the matter of irrigation it would be possible that the crop in U.P. and Bihar would be normal. Efforts are being and will be made in this direction to meet internal demand and exports. The target of 33 lakh tons is being kept in view. Having regard to the production of over three million tons attained in 1960-61 and the additional capacity which has since been installed, there should not be much difficulty in achieving the target provided the existing crop prospects are maintained. The State Governments have been apprised of the production targets that they should aim at. The Government also realises that in order to achieve this production incentives will have to be given for early start of factories as was done in 1959-60 and maximising production by making it worth while for the factories to work beyond the normal season as was done in 1959-60 and 1960-61. By giving this incentive in one year we have been able to get an increased production in the year 1959-60 of 3 lakh tons and in 1960-61 we have been able to get 6 lakh tons increased production. So it is not an unattainable goal thai we have kept before us. Regarding this problem of incentives, in a way we have finalised our proposals in the Ministry of Food and Agriculture. They are being discussed with other Ministries, the Finance Ministry and the Planning Commission, and we hope to finalise the proposals within a few days and take them fo the Cabinet, and I may assure the hon. House that these incentives will be annonuced without any avoidable delay. After all we have been planning for production from the month of October so that by September itself all these steps would certainly be announced.

Then there is this question of diversion to jaggery. In fact as I have indicated, we have to keep a balance between jaggery, khandsari and crystal sugar. Now the shortage is keenly felt in the matter of crystal sugar. We have to meet our export commitments. We have to meet our internal consumption of 26 to 27 lakh tons. At least we have to have 2 lakh tons as carryover. Keeping these things in view we have to see that as much diversion as possible is made to the manufacture of crystal sugar. The steps that we have formulated have been discussed with the various Chief Ministers of States and Agriculture Ministers, and they have also in a way fallen in line with our proposals. Now the diversion to crystal sugar can be effected by following two ways: by giving direct incentives, that ls additional sugarcane price, to th»

grower, and by giving incentives tc the factories which would enable them to pay additional sugarcane price to the grower. Gur and khandsari manufacturer has a definite advantage over the factories. In fact that advantage has to be lessened to some extent, and I I hope the hon. House will co-operate with both the State Governments and the Central Government in seeing that the jaggery manufacturer and the khandsari manufacturer do not have an undue advantage over the sugar factories. So there would be in the matter of purchase a levy of purchase tax or in the matter of excise duties the burden would be increased for the jaggery producer and the khandsari producer so that they may not have an undue competitive advantage over the factory producer. All the steps that are possible are being taken. In fact Shri Vajpayee complained that a long term view was not taken. A long term view is taken. The remedy is increased production of sugarcane from the existing acreage. In fact each pilot project in this respect, that is a sort of a package programme, will involve an outlay of Rs. 3 lakhs. For intensive cultivation of sugarcane in the factory's area of about 4000 acres a plan has been drawn up ind accepted and it is being worked out in U.P. involving an outlay of Rs. 1 crore. One-third of that expenditure will be met by the Central Government. As has been said by Shri Sri Rama Reddy water i_s the main problem for the U.P. grower. If as a result of these steps that are being taken is made available to the sugarcane cultivator in U. P., in fact we may be able even to 5 P.M. exceed these 33 lakh tons. So, all possible steps are being taken to increase th_e installed capacity and to give incentives, so that $ther_e$ is an increase in sugarcane production.

I hope, Sir, that the hon. Member is satisfied with regard to the short-term and the long-term steps that are being taken by the Government.

श्री ए० बी० वाजपेयी : उपसभाध्यक्ष जी, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा । जिन माननीय सदस्यों ने इस विवाद में भाग लिया है उन सब को मैं धन्यवाद देता हूं ।

मंत्री महोदय का भाषण बड़ा निराशाजनक रहा । उन्होंने तोड़ मरोड़ कर तर्क को पेश करने की कोशिश की है । यह कहना कि मौसम की वजह से गन्ने की पैदावार घट गई सत्य नहीं है । हमारे देश में मौसम की आड़ ले कर हर एक विफलता को छिपाने का प्रयास किया जाता है । चाहे वह गन्ने की पैदावार हो या गल्ले की पैदावार हो, जब पैदावार कम होती है तब मौसम को दोष दिया जाता है लेकिन जब पैदावार बढती है तब मौसम को कोई बधाई नहीं देता, तब शासन अपनी पीठ ठोकता है—यह दोनों बातें साथ नहीं चल सकतीं । जब आर्थिक नियोजन चल रहा है तब मौसम पर निर्भरता कम होती जानी चाहिये । लेकिन जहां तक गन्ने के उत्पादन का प्रश्न है अभी तक शासन ऐसी पक्की व्यवस्था नहीं कर सका कि जितना उत्पादन आवश्यक हो उतना उत्पादन हो और उत्पादन की कमी अनुभव में न आये । जहां तक १९६१–६२ में चीनी के उत्पादन पर नियंत्रण लगाने का सवाल है, मंत्री महोदय ने जो तस्वीर पेश की है वह पूरी तस्वीर नहीं है । एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बना कि गन्ना पैदा करना हित में नहीं है और अगर गन्ना पैदा किया जायगा तो उस से लाभ नहीं होगा । मंत्री महोदय हवाला देते हैं कि गन्ने की एकड़ पैदावार बढ गई लेकिन वह इस बात पर भी बल देते हैं कि प्रति एकड़ पैदावार बढ़नी चाहिये, गन्ने की एकड़ पैदावार बढ गई या उसका केवल क्षेत्रफल बढ़ गया, इसलिये उन्होंने यह कैसे सोचा कि हमें जितना गन्ना चाहिये उतना गन्ना मिलेगा । उन्होंने भविष्य के बारे में आश्वासन दिये हैं लेकिन मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि ३३ लाख टन का उत्पादन अगले वर्ष करना यह

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

कठिन बात है । इस कठिन बात को सरकार कैसे पूरा करती है यह तो भविष्य बतायेगा लेकिन अगर केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें इस सम्बन्ध में समुचित नीति नहीं अपनायेंगी और गन्ना उत्पादकों को जो सुविधायें दी जानी चाहियें उन्हें देने में शीघ्रता नहीं करेंगी तो गन्ने का उत्पादन इतना नहीं होगा कि आप ३३ लाख टन चीनी पैदा कर सकें ।

सरकार का अभी तक इस सम्बन्ध में रिकार्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम ने जो चीनी उत्पादन का लक्ष्य रखा है अब उस से भी आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उस के अनुरूप क्या हम धनराशि दे रहे हैं, क्या किसानों को सुविधायें दे रहे हैं ? मैं तो आशा करता था कि इस विवाद में मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि किसानों के गन्ने के मूल्य में कितनी वृद्धि की जा रही है लेकिन शायद यह निर्णय नहीं कर सके हैं । उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें सिफारिश करती हैं कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाये मगर केन्द्रीय सरकार नहीं बढ़ाती है ।

विदेशों में हम चीनी का निर्यात करें, विदेशी मुद्रा हमें चाहिये मगर किस कीमत पर चाहिये ? पिछले दो तीन महीनों में जो चीनी संकट पैदा हुआ है उस में लोगों का करोड़ों रुपया चोर-बाजारों और मुनाफाखोरों के हाथ में चला गया । हम ने जनता को परेशान किया । शादी विवाह में लोगों ने दो रुपया सेर चीनी गांवों में खरीदी और आज भी गांव की जनता की मांग को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं । मैं आशा करता हूं कि पूरा ३३ लाख टन उत्पादन करने का लक्ष्य पूरा हो लेकिन उसके लिये कौन से ठोस कदम उठाये जा रहे हैं, इस सम्बन्ध में सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिये । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at four minutes past five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 27th August, 1963.